● वर्ष-3
● अंक-113
रायपुर, बुधवार
20 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जब अपनों को दें...

रमन सिंह निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरूआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन सभी विधायकों ने शपथ ली।

सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत सभी 90 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान अधिकतर विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने पद की शपथ ली। इसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधायकों को शपथ दिलाई। सदन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित अधिकतर विधायकों ने राजभाषा छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम

विधायकों ने ली शपथ

अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। इसके अलावा विक्रम उसेंडी, धरमजीत सिंह, रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, रायगढ़ से भाजपा विधायक ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ी में, खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल छत्तीसगढ़ी समेत सभी विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली।

वही बस्तर संभाग से आने वाले विधायक लता उसेंडी, केदार कश्यप, चैतराम अटामी के अलावा गुरु खुशवंत, प्रेमचंद पटेल और विद्यावती सिदार ने भी संस्कृत में शपथ ली। लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू और रेणुका सिंह ने हिंदी में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष को पहले शपथ दिलाया। 90 विधायकों के शपथ के बाद स्पीकर पद के लिए रमन सिंह के नाम पर 5 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें सत्तापक्ष की ओर से विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, भावना बोहरा, अजय चंद्राकर ने प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणदास महंत ने रमन सिंह के विधानसभा अध्यक्ष पर प्रस्ताव पेश किया।

इसके बाद रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। भटगांव विधानसभा से विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा प्रवेश के दौरान द्वार पर माथा टेक कर प्रवेश किया वही धरसीवां विधायक अनुज शर्मा पैदल चलकर विधानसभा पहुंचे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ल ने नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने की मांग की थी। विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा।

यही आचरण रहा तो और भी कम सीटों के साथ विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर संसद में सुरक्षा चूक की घटना को मौन और अप्रत्यक्ष समर्थन देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि उनका यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में वे और भी कम सीटों के साथ विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे. इस साल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रचार अभियान का विषय तय किया और साथ ही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस यानी 'इंडिया' गठबंधन पर उनकी बैठक के मद्देनजर निशाना भी साधा.

संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे हालिया विधानसभा चुनावों में हार से हताश होकर इस घटना को 'राजनीतिक तूल% दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है लेकिन सरकार का लक्ष्य भारत का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ''कुछ लोग भाजपा को सत्ता से हटाने के इरादे से एकजुट हो रहे हैं जबकि हम देशभक्त हैं और भारत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. वे सरकार को हटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि हम भारत की भलाई के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में विपक्ष का यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या और कम हो जाना सुनिश्चित है जबकि भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ेगी. सभागार में कुछ खाली पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें 2024 के चुनावों के बाद भरा जाएगा.

उन्होंने 13 दिसंबर को दो लोगों के दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदने और कैन से धुआं फैलाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि इस कृत्य की एकजुट होकर निंदा की जानी चाहिए थी.

एक सूत्र के मुताबिक, उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, मैं जो देख रहा हूं वह यह है कि विपक्ष चुनावों में हारने की अपनी हताशा को बाहर निकाल रहा है और पूरी घटना को राजनीतिक रंग दे रहा है. वे इसे मौन और अप्रत्यक्ष समर्थन भी दे रहे हैं जो चिंताजनक है. घटना का समर्थन करना और इस तरह की बातें कहना कि वे और क्या कर सकते थे, चिंताजनक और निंदनीय है.

उन्होंने कहा, हमें अपनी भाषा को नियंत्रण में रखते हुए और लोकतंत्र की सीमाओं के भीतर रहते हुए विपक्ष को बेनकाब करना चाहिए. आने वाले दिनों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग भाग ले रहे हैं या नहीं, हमें संसद की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए आ रहे हैं. पार्टी नेताओं के अनुसार, विपक्षी दलों की तीखी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा होता अगर विपक्ष इन चर्चाओं में भाग लेता लेकिन अच्छे काम शायद उनके भाग्य में नहीं हैं.

ममता ने प्रधानमंत्री के लिए खरगे के नाम का दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के मकसद से बने विपक्षी दलों के 'इंडिया' अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार (19 नवंबर) को दिल्ली में हुई. इस मीटिंग में 'इंडिया' अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम रखा गया. सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खरगे के नाम का प्रस्ताव रखा. आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया. ममता बनर्जी ने इसके साथ ही 'इंडिया' अलायंस के कंविनर के लिए भी मल्लिकार्जुन खरगे के नाम का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, मल्लिकार्जुन खरगे ने

विनम्रतापूर्वक 'इंडिया' अलायंस का चेहरा बनने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं. खरगे ने कहा कि पहले चुनाव जीतकर आएंगे, उसके बाद पीएम उम्मीदवार तय करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, दलित चेहरा होने की वजह से खरगे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया गया है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, खरगे के नाम पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. इसके साथ ही 'इंडिया' अलायंस की मीटिंग में सीट शेयरिंग फॉर्मूले, अलायंस के कोऑर्डिनेटर, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग को लेकर डिटेल चर्चा तो हुई, मगर आज की मीटिंग में कुछ फाइनल नहीं हो पाया. सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी समेत 'इंडिया'अलायंस के कई दलों ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी है.

प्रमुख समाचार

कोरोना बढ़ा रहा टेंशन इस महीने हुई 10 मौतें

नई दिल्ली. कोरोना महामारी एक बार फिर देश में अपने पैर पसार रहा है। सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में कहर बरपाने के बाद इसके नए वेरिएंट जेएन-1 ने देश में भी दस्तक के दी है। केरल में इस नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। उधर, कर्नाटक सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी है। महामारी की बढ़ती संभावनाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, केरल में कोरोना केस सप्ताह भर में तीन गुना तक बढ़ गए हैं। जबकि 1 से 17 दिसंबर तक 10 मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 20 दिसंबर को समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सरकार की चिंता नए वेरिएंट जेएन.1 को लेकर है, जो हाल ही में केरल में एक 79 वर्षीय महिला में पाया गया था। यह कोरोना का सबसे नया वेरिएंट है, जो सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में जमकर कहर बरपा रहा है।

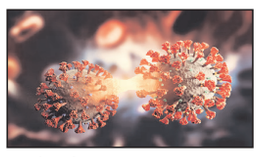

फिलीपींस-ब्राजील और मिस्र की आकाश मिसाइल में बढ़ी रुचि

नई दिल्ली। आर्मेनिया के साथ आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को लेकर हुए सौदे के बाद फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र भी इस मिसाइल प्रणाली की खरीद में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि आकाश मिसाइल प्रणाली को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऑर्डर पहले ही हो चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि अगले कुछ महीनों में आर्मेनिया को डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच, ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस सहित कई देशों ने आकाश मिसाइल प्रणाली में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में भी ऐसे देश हैं जिन्होंने आकाश हथियार प्रणाली की क्षमताओं और परीक्षणों में रुचि दिखाई है। हाल ही में आकाश मिसाइल का एक परीक्षण किया गया था। जहां एक आकाश मिसाइल ने चार लक्ष्यों (मानव रहित हवाई लक्ष्य) पर एक साथ निशाना साधा था। यह प्रदर्शन 12 दिसंबर को सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन पर अस्त्रशक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद डीआरडीओ ने दिखाया कि आकाश एक साथ चार निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है।

लोकसभा में केंद्रीय वस्तु व सेवा कर संशोधन विधेयक पास

नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है। लोकसभा ने 19 दिसंबर (मंगलवार) को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान करों के अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 को पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। यह विधेयक टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव के साथ या उसके बिना सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित कानूनों का प्रावधान करेगा, जो एक निर्धारित समय के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

भाजपा ने सहयोगियों को संघ मुख्यालय के लिए बुलाया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों शिवसेना और राकांपा के अजित पवार गुट को उनके विधायकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर को श्रद्धांजलि देने के लिए नागपुर के रेशमबाग में डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति में आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम मंगलवार को सुबह आठ बजे निर्धारित है। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक और मुंबई विधायक आशीष शेलार ने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूहों के विधायकों को आमंत्रित किया। पत्र में सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों को संबोधित एक पंक्ति में कहा गया है कि उपस्थिति अनिवार्य है। राकांपा के अजित पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री का सुबह आठ बजे स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है और इसलिए, उनके संघ के स्मारक की यात्रा में शामिल होने की संभावना नहीं है। वरिष्ठ नेता ने कहा, हमने पहले ही उनके (अजित पवार के) आधिकारिक आवास पर संपादकों के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि वह जाएंगे या नहीं।

तमिलनाडु में बारिश से, 10 लोगों की मौत; 809 ट्रेन यात्रियों को बचाया गया

चेन्नई/ मदुरै। तमिलनाडु अब तक चक्रवाती तूफान मिचौंग के प्रभाव से उबर भी नहीं पाया है। इस बीच राज्य में एक बार फिर भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि भारी बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिव दास मीना ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का भारी बारिश का पूर्वानुमान भी गलत था, क्योंकि दो दिनों के भीतर प्रभावित जिलों में 1150 मिमी बारिश हुई। उन्होंने कहा कि दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों में कुछ की जान दीवार गिरने से तो कुछ की मौत बिजली का करंट लगने से हुई।

वक्त फिसलता जा रहा है विपक्ष के हाथ से

अभय कुमार दुबे

अगर पंद्रह जनवरी तक राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने अपनी हुलिया दुरुस्त नहीं की तो 2024 के लिए होने वाली मोर्चाबंदी के संदर्भ में विपक्ष बहुत पिछड़ जाएगा। समय विपक्ष के हाथ से फिसलता जा रहा है। यह समय फिर से लौट कर नहीं आएगा। अगर विपक्ष मोदी के रास्ते में बाधाएं नहीं खड़ा कर पाया, तो 2029 के चुनाव के पहले उसकी शक्ल-सूरत केवल औपचारिक रह जाएगी। अपनी हुलिया दुरुस्त करने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष अगर करना चाहे तो थोड़े-बहुत हेरफेर के साथ तीन काम कर सकता है।

राहुल गांधी 28 की रैली में मंच से कह सकते हैं कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और उनकी दिलचस्पी केवल विपक्षी एकता के लिए काम करने की है। यह कहना इसलिए जरूरी है कि जब लोकनीति-सीएसडीएस के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के वोटरों से पूछा कि उन्होंने किसके नाम पर वोट दिए तो जवाब मिला कि कोई 20 फीसदी लोगों ने तो मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिए हैं, पर राहुल के नाम पर केवल दो फीसदी लोगों ने ही कांग्रेस को वोट दिए हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल गांधी मोदी से बहुत पीछे हैं। दूसरा काम यह किया जा सकता है कि बिना देर किए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) बना कर सार्वजनिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। इस काम में किसी भी तरह के मतभेद की संभावना बहुत कम है।

सोनिया गांधी नौ केंद्रीय मुद्दे बहुत पहले जारी कर चुकी हैं। बस, क्षेत्रीय शक्तियों से पूछना बाकी है कि वे अपने-अपने कौन से मुद्दे जुड़वाना चाहती है। जैसे ही यह सीएमपी बने, वैसे ही इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को मंच से घोषित करना होगा कि यही उनका भी घोषणापत्र होगा। वे अलग से अपना घोषणापत्र जारी नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि जब नब्बे के दशक में अटल-आडवाणी ने एनडीए बनाया था तो भाजपा ने अपना घोषणापत्र अलग से जारी करने से इंकार कर दिया था। जैसे ही गठबंधन के नेतागण ऐसा करेंगे, वैसे ही विपक्ष की राष्ट्रीय एकता का नजारा स्पष्ट हो कर देश की जनता के सामने आ जाएगा।

तीसरा काम इस गठबंधन को यह करना चाहिए कि केवल बड़े-बड़े दलों तक ही सीमित न रह कर छोटे-छोटे दलों को अपने आगोश में लेने की योजना पर काम किया जाए। दरअसल, उन्हें राजस्थान में विधानसभा चुनाव से सबक हासिल करना होगा। राजस्थान में अगर

कांग्रेस ने बसपा, बेनीवाल की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी और अन्य छोटी-छोटी पार्टियों को अपने साथ ले लिया होता तो इस समय भजनलाल शर्मा नहीं बल्कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के आवास में बैठे होते। दरअसल, राजस्थान की पराजय एक रणनीतिक पराजय भी है। 43 सीटें ऐसी हैं जिन पर विजेता भाजपा और पराजित कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर किसी छोटी पार्टी के वोटों से कम है। कहना न होगा कि लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को कम वोट मिलने की संभावना रहती है, फिर भी इन्हें साथ रखने से विपक्ष का जमावड़ा बड़ा बनता है और गैर-भाजपा मतों का ध्रुवीकरण ठीक से हो जाता है।

इसी के साथ कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं वाले प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण आदिवासी नेताओं या किसी एक बड़े नेता की खोज शुरू कर देना चाहिए। भाजपा ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति और एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना कर अपना दीर्घकालीन दांव खेल दिया है। अभी तक कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं दिख रही है। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ को छोड़ कर कांग्रेस आदिवासी वोटों में भाजपा से आगे है। राजस्थान में उसके पास आदिवासियों के वोटों के संदर्भ में पांच प्रतिशत अंकों की बढ़त है, और मध्य प्रदेश में तो यह बढ़त बारह की है। भाजपा यहां जीती इसलिए है कि उसने अपने आदिवासी वोटों में ऊंची जाति के और ओबीसी वोटों को काफी जोड़ा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब इसका समय नहीं रह गया है। यह समय उनकी छवि सुधारने का नहीं है। यह विपक्षी एकता की छवि सुधारने का है। न ही यह समय मुसलमान वोटरों पर बहुत ज्यादा फोकस में समय गंवाने का है। मुसलमान तो पहले से ही कांग्रेस के साथ कटिबद्धता के साथ हैं।

मसलन, राजस्थान में 90 फीसदी और मध्य प्रदेश में 85 फीसदी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन, वे चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने में सफल नहीं रहे। इसलिए कि भाजपा ने ज्यादा बड़ी हिंदू एकता कर दिखाई। कांग्रेस की चुनौती इस हिंदू एकता में सेंध लगाने की है, न कि मुसलमान वोट प्राप्त करने की। ऊंची जातियों में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। ओबीसी जातियों में भी वह काफी आगे है। साठ के दशक से द्विज-ओबीसी एकता का जो फार्मूला आजमाया जा रहा है, वह संघ परिवार के अनथक प्रयासों से धरती पर उतरता दिख रहा है। जब तक यह समीकरण नहीं टूटेगा, मोदी और भाजपा को हराना मुमकिन नहीं होगा।

बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

नक्सलियों ने बीजीएल से किया हमला, सर्चिंग के दौरान 5 नग बीजीएल बरामद

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सल घटनाएं बढ़ गई है। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। चिन्नागेलुर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। बीजापुर में सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम चिन्नागेलुर की तरफ एरिया डॉमिनेशन के लिए निकली हुई ती। इसी दौरान चिन्नागेलुर के जंगल में छिपे बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बीजीएल (बैरल ग्रेनड लॉचर) से जवानों पर हमला किया। जवानों ने भी नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। जिसके बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर जंगल में भाग गए। जवानों ने मौके की सर्चिंग के दौरान 5 नग बीजीएल बरामद किया है। बीजापुर एसपी अंजनेय वाष्णेय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जवान सुरक्षित हैं, इलाके की सर्चिंग जारी है।

छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली घटनाएं हो रही है। नई सरकार बनने के बाद सीएम के शपथ ग्रहण के दिन भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें नारायणपुर में एक जवान शहीद हो गया। इसके दूसरे दिन कांकेर में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। जवानों के शहीद होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम ने नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए।

सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। बसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है। नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है। जिसके चलते

माओवादी कायराना हरकत कर रहे हैं। जैसे पहले 15 वर्षों में हम नक्सलियों से लड़ाई लड़ी है। इस बार डबल इंजन की सरकार है। उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ आने वाले समय में नक्सलियों से लड़ाई लड़ेंगे।

बेहतर रणनीति के साथ नक्सल अभियान संचालित करने बैठक

नारायणपुर। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाकों में बेहतर तालमेल के साथ संयुक्त रूप से नक्सल उन्मूलन अभियान को संपादित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद ने नारायणपुर जिला मुख्यालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में नक्सल अभियान को आगामी समय में और बेहतर रणनीति के साथ अभियान संचालित करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि शासन-प्रशासन के मंशानुरूप नक्सल अभियान में तेजी आयेगी। इस समीक्षा/समन्वय बैठक में विवेकानंद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान के साथ सुंदरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, साकेत कुमार पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ, बालाजी राव उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर रेंज, पुलिस अधीक्षक कांकेर दिव्यांग पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा एवं आईटीबीपी एवं बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे । प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायणपुर भ्रमण के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान विवेकानंद के साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पी., साकेत कुमार पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेदरे सीआरपीएफ कैंप, जिला-सुकमा पहुंचकर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं सीआरपीएफ कोबरा के अधिकारियों के साथ मिलकर बेदरे एरिया में हुए मुठभेड़ के संबंध में अभियान में शामिल अधिकारियों, जवानों से रूबरू होकर अभियान की समीक्षा की गई। आगामी समय में नक्सल उन्मूलन अभियान पर प्रभावी कार्यवाही, नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई।

बेमेतरा में एमपी से नकली खाद तस्करी की आशंका

पुलिस ने खाद समेत जब्त किया ट्रक

बेमेतरा। सिटी कोतवाली पुलिस ने ट्रक में अवैध रूप से अमानक खाद डीएपी परिवहन करने की सूचना पर कार्रवाई की है। जबलपुर - रायपुर नेशनल हाईवे में ट्रक को पुलिस ने अवैध खाद समेत जब्त किया है। जिसे सिटी कोतवाली थाने में सुरक्षित रखा गया है। वहीं ट्रक में लोड किये गए दो अलग-अलग किस्म के डीएपी खाद की बेमेतरा कृषि विभाग ने सैंपल लिया है।

मामला बीती रात का है। जहां जबलपुर की ओर से आ रही ट्रक में अमानक खाद के अवैध रूप से परिवहन की सूचना सिटी कोतवाली थाने को मिली। जिसके बाद पुलिस ने नवागढ़ तिराहा में घेराबंदी करके ट्रक को सिटी कोतवाली ले आई है। जिसमें 600 बोरी डीएपी खाद है। जो अलग-अलग 2 कंपनियों की बताई जा रही है। वहीं एक खाद काले रंग की है और दूसरी खाद सफेद रंग की है। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने डीएपी की गुणवत्ता की जांच के लिए कृषि विभाग को जांच के लिए बुलाया है। जहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने थाना पहुंचकर डीएपी के सैम्पल लिए हैं। अब आगे दोनों खाद के सैम्पल की जांच होगी। जिसके बाद आगे का कार्रवाई की जाएगी।

बेमेतरा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में 600 बोरी डीएपी है। जो अलग-अलग कंपनियों के हैं। लेकिन बिल में डीएपी का उल्लेख न कर जैविक खाद लिखकर भेजा गया है। जिससे खाद के अमानक होने की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर बेमेतरा एसडीओपी

एसडीओपी मनोज कुमार तिर्की ने कहा वाहन में अमानक खाद की सूचना पर ट्रक थाने में रखा गया है। जिसमें 600 बोरी डीएपी है। जो करीब 4 से 5 लाख रुपए के आसपास की बताई जा रही है।

कृषि विभाग ने खाद का सैम्पल लिया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई जारी है वहीं कृषि विभाग एसडीओ श्यामलाल साहू ने कहा कि डीएपी का सैम्पल लिया गया है। लैब में जांच के बाद गुणवत्ता का पता चलेगा।

किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस की जांच टीम पहुंची मृतक के घर

नारायणपुर। कुकड़ाझोर गांव में बीते 12 दिसंबर को एक किसान के आत्महत्या करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच टीम मृत किसान हीरु बढ़ई के घर पहुंची और यहां उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया साथ ही परिजनों के साथ-साथ गांव वाले के भी बयान दर्ज किए, कांग्रेस की जांच टीम ने अपने प्रारंभिक जांच में पाया कि किसान ने सवा लाख रुपये के कर्ज नही चुका पाने के चलते कीटनाशक दवाई खाकर आत्महत्या कर ली है। जांच समिति के सदस्यों का कहना है कि वह जल्द ही परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज करने के बाद एक रिपोर्ट बना कर पीसीसी को सौपेंगे।

जांच कमेटी के संयोजक लखेश्वर बघेल ने बताया कि किसान ने कर्ज तले दबे होने से आत्महत्या करने की कांग्रेस के प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है। उन्होने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर पता चला है कि किसान हीरू अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अकेले करता था। पत्नी और दोनो बेटों के साथ वह अपनी सास का भी पालन पोषण करता था, हीरु के पास 9 एकड़ खेत है और इस साल मौसम की बेरुखी के चलते उसके 9 एकड़ खेत में केवल 70 बोरी ही धान की पैदावार हुई। कुछ दिन पहले ही बैंक की तरफ से हीरू पर 1 लाख 24 हजार रूपये का कर्ज चुकाने का नोटिस भेजा गया, जिसे लेकर वह चिंतित रहा करता था। बेटे के विवाह के लिए रकम का इंतजाम कैसे होगा, इस बात का जिक्र वह प्रायः अपने परिजनों के सामने करता था और आखिरकार तनाव में आकर किसान हीरू ने इस तरह का कदम उठाया। लखेश्वर बघेल का कहना है कि पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे पीसीसी को सौपा जाएगा और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे कांग्रेस के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा।

बच्चों के भविष्य से खेल रहा सिस्टम 79 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक

कोई पीकर आता है दारू, कोई मोबाइल में करता है टाइम पास

बालोद। जिले के डौण्डी विकासखंड स्थित ग्राम आड़ेझर शासकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक और ग्रामीणों ने स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक एके कोमर्रा और शिक्षिका हेमेश्वरी श्रीवास के खिलाफ मोर्चा खोल बच्चों को आज स्कूल भेजना बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार, स्कूल में कक्षा पहली से पांचवी तक 79 बच्चे अध्यनरत हैं। जहां एक प्रभारी प्रधान पाठक सहित कुल तीन शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं।

दरअसल, 13 दिसंबर को ग्रामीणों प्रभारी प्रधान पाठक को शराब पीकर स्कूल आने और शिक्षिका को स्कूल में आने के बाद दिनभर मोबाइल में व्यस्त रहने की बात करते हुए बच्चों के शिक्षा के स्तर गिरने की बात कह थी। दोनों शिक्षक को हटाने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया था। जिस पर अधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लेने से आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया।

हालांकि, जैसे ही स्कूल बंद होने की जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लगी तो बीईओ जेएस भारद्वाज और बीआरसी सच्चिदानंद शर्मा तुरंत स्कूल पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की। साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रभारी प्रधान पाठक को हटाया जाएगा। साथ ही मैडम हेमेश्वरी श्रीवास एक मौका देते हुए जमकर फटकार लगाई गई। अधिकारियों की मानें तो ग्रामीणों को मना लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि ग्रामीणों अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या स्कूल में सन्नाटा ही पसरा रहेगा।

लोकेश का पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार

पीएम आवास योजना से बनाया अपना मकान

बेमेतरा। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक व्यवस्थित आशियाना हो, जिसमें वह सुकून से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर सके। ऐसा ही सपना बेमेतरा के ग्राम चमारी, निवासी श्री लोकेश साहू का रहा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हकीकत में साकार हुआ।

लोकेश ने बताया कि पहले कच्चे मकान में कई सालों से रहते आए हैं, छप्पर की छत होने की वजह से उस मकान में बरसात के मौसम में पानी रिस कर आता था, जिससे उन्हें रहने में भारी समस्या होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे पेशे से मजदूर है और घर में जब बरसात के मौसम में पानी टपकता, तो उस वजह से कभी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, नींद पूरी न होने की वजह से मजदूरी का काम भी बहुत अधिक प्रभावित होता था।

इन सब कारणों की वजह से लंबे समय से उनका सपना रहा कि स्वयं का एक पक्का मकान बनाया जाए। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने अपना पक्का मकान बनाने का सपना साकार किया। अब वे निश्चिंत होकर परिवार के साथ स्वयं के मकान में रहने लगे हैं। लोकेश ने सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आर्थिक तंगी से गुजर रहे उन लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल रहा है जो मिट्टी के जर्जर मकानों में रह रहे थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सीएम साय के निर्देश पर यूपी से लौटे पहाड़ी कोरवा युवा

सरगुजा। उत्तरप्रदेश के बागपत जिले में गन्ने के खेतों में काम कर रहे पहाड़ी कोरवा युवा सुरक्षित छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। इन्होंने वीडियो बनाकर सहायता की अपील छत्तीसगढ़ सरकार से की थी। वीडियो पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरगुजा जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पहाड़ी कोरवा युवाओं को सकुशल छत्तीसगढ़ लाने की कार्यवाही की। गौरतलब है कि सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल एसडीएम रवि राही को उत्तर प्रदेश के बागपत भेजा। राही ने बागपत जिला प्रशासन से सम्पर्क कर इन युवाओं को लेकर सरगुजा लौट आएं हैं। पांचों युवा संरक्षित जनजाति समूह पहाड़ी कोरवा से हैं। पहाड़ी कोरवा राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति समूह हैं।

छत्तीसगढ़ में सरकार बदली लेकिन कब बदलेगा सिस्टम

अंबिकापुर। रनपुरकाल गांव में पंडो जनजाति की महिला को प्रसव की जैसे ही दिक्कत हुई गांव वाले मरीज को खटिया पर डालकर तुरंत अस्पताल के लिए भागे। करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी तय गांव वालों ने प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया जिसके बाद महिला को इलाज मिल पाया। दिन का वक्त था तो महिला को लखनपुरी की डायर 112 की मदद भी मिल गई। रात के वक्त अगर गांव में किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी तो मरीज को कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। महिला को खटिया पर डालकर एंबुलेंस तक ले जाने का वीडियो अब तेज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबिकापुर में आज भी ऐसे दर्जनों गांव हैं, जहां एंबुलेंस नहीं पहुंचती है। स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस और जहां कर्मचारी नहीं पहुंचते, वहां गांव के लोग ही खटिया को एंबुलेंस बनाते हैं। ग्रामीण खुद स्वास्थ्य विभाग की भूमिका में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। किसी महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना होता है, तो उस वक्त गांव के ये देवदूत फरिश्ता बनकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं।

जगदलपुर के शहीद पार्क के पास हुआ बड़ा हादसा

जगदलपुर। शहर के मध्य स्थित शहीद पार्क के सामने लगे सिग्नल पोल में बीती रात एक तेज रफ्तार कार जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार दो युवकों की जहां मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच घायलों को उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले गई। वहीं मृतकों के शव को मेकाज पीएम के लिए भिजवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मेन रोड निवासी राहुल पवार पिता विनोद पवार 24 वर्ष निवासी व वैभव गुप्ता 24 वर्ष निवासी ठाकुर रोड निवासी अपने अन्य दो दोस्तों के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने आड़ावाल की ओर गए हुए थे। रात करीब एक बजे के समय वापस कुम्हारपारा से मुख्य मार्ग की ओर वापस आ रहे थे कि शहीद पार्क के पास लगे सिग्नल पोल से जा टकराए। हादसा इतना जबरदस्त था कि वैभव और राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों साथी घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव मेकाज भिजवाया।

छत्तीसगढ़ में चोरों का आतंक चोर डीजल भी नहीं छोड़ रहे

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डीजल चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गेवरा खदान में डीजल चोर गिरोह का आतंक सामने आया है। जहां डीजल चोर गिरोह के बदमाश हथियार लेकर घुसते हैं। गेवरा खदान के बी टू कोल स्टोक से बुलेरों समेत 225 लीटर डीजल सीआईएसएफ ने पकड़ा है। गेवरा खदान में डीजल चोरी की घटना लगातार घट रही है। सीआईएसएफ के सर्चिंग के दौरान डीजल चोर गिरोह वाहन छोड़ भाग निकले। जब्त किए गए बुलेरो वाहन में 35 लीटर के पांच डिब्बों में 225 लीटर डीजल पुलिस ने सौंप दिया दिया है। जिसकी अनुमानित कीमत 25500 बताई जा रही है। दीपका पुलिस डीजल चोरी के मामले में धारा 379, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रही है।

बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के मेऊभाटा के पास मेन रोड में दो बाइक में आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई है। जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। वहीं महिला सहित तीन लोगों घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए पामगढ़ अस्पताल लाया गया। गंभीर चोट लगने के बाद उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम खिसोरा के रहने वाला करण कोसले अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गिरौधपूरी घूमने गए हुए थे। तीनों एक बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक में सवार मनोज संडे अपनी पत्नी के साथ शिवरीनारायण की ओर जा रहे थे। दोनों की बाइक मेऊभाटा मेन रोड के पास आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक की टक्कर से बाइक सवार सभी एक दूसरे से दूर जा गिरे। सभी घायलों को उपचार के लिए पामगढ़ अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत करण कोसले और मनोज संडे को मृत घोषित कर दिया।

तेंदुआ खाल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, दो फरार

गरियाबंद। दिनांक 18 दिसम्बर को मुखबिर से सूचना मिली की वन परिक्षेत्र तौरेंगा (बफर), सर्कल गाजीमुड़ा के अंतर्गत ग्राम कोचेंगा पेट्रोलिंग केम्प के नीचे कोचेंगा गाजीमुड़ा मार्ग के बीच में 1 नग तेन्दुआ खाल की खरीदी/बिक्री करने वाले हैं। सूचना मिलते ही एण्टी पोचिंग टीम उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के सदस्य तत्काल मौके पर पहुंचे , जहां एक व्यक्ति बुध्दू राम पिता घांसीराम, जाति गोंड़, उम्र 47 वर्ष, ग्राम गाजीमुड़ा, थाना शोभा, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.) को 1 नग तेन्दुआ खाल के साथ पकड़ा गया , बताया जा रहा है कि मौके से उसके दो साथी फरार हो गये। बुध्दू राम पिता घांसीराम,जाति गोंड़ को मौके से पकड़कर विस्तृत पूछताछ हेतु परिक्षेत्र कार्यालय तौरेंगा, मुकाम मैनपुर लाया गया। इन सभी के विरुध्द वन अपराध

पी.ओ.आर. क्रमांक-25/03 दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को पंजीबध्द कर आरोपी बुध्दू राम पिता घांसी राम को विवेचना अधिकारी गौरीशंकर भोई उप वनक्षेत्रपाल के द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 19 दिसम्बर 2023 को माननीनय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गरियाबंद के समक्ष पेश किया जायेगा।

इस कार्यवाही में एण्टी पोचिंग टीम उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के गोपाल कश्यप, सहायक संचालक उदंती, मैनपुर नोडल अधिकारी, चंद्रबली ध्रुव, उपवनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी, ओमप्रकाश राव वनरक्षक, चुरामन घृतलहरे, वनरक्षक, फलेश्वर दिवान वनरक्षक, राकेश सिन्हा वनरक्षक, विरेन्द्र ध्रुव वनरक्षक एवं परिक्षेत्र तौरेंगा अंतर्गत राकेश सिंह परिहार, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी तौरंगा, नितेश कुमार सारथी वनपाल, तुकेश्वर यदु वनपाल, खिलेश कुमार यादव वनरक्षक, सुरज कुमार पात्र दे. वे.भो. उपस्थित रहे।पूरी कार्यवाही सुधीर अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी रायपुर छ.ग.), श्रीमती एम. मर्शीबेला मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर एवं वरूण जैन, उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के कुशल मार्गदर्शन में की गई।

साय के सीएम बनने के बाद अब शिक्षा में भी दिखने लगी कसावट

■ एकल शिक्षकी स्कूल में हुई नई पदस्थाना

कांसाबेल। कुनकुरी विधायक विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में लगातार प्रशासनिक कसावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य के साथ ही अब शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

शासकीय प्राथमिक शाला तामासिंघा में विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या 48 है और वहां केवल एक प्रधान पाठक पदस्थ हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफी समस्या आ रही थी। इसे लेकर बच्चों के अभिभावक काफी चिंतित थे। इन अभिभावकों ने मुख्यमंत्री निवास (बगिया) पहुंचकर एक आवेदन दिया था, जिस पर सीएम हाउस से कलेक्टर को एकल शिक्षकी शाला की समस्या से अवगत कराते हुए तत्काल व्यवस्था बनाने को कहा गया था।

कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उनके निर्देश पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बंदरचुवा के प्राचार्य ने प्राथमिक कन्या शाला बंदरचुवा की सहायक शिक्षक सरिता खाखा को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय प्राथमिक शाला तामासिंघा में अध्यापन कार्य करने के लिए आदेशित किया है। साथ ही सरिता खाखा को उक्त संस्था में अपनी उपस्थिति देने को कहा है। समस्या का समाधान तत्काल होने पर अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के छठे विधानसभा अध्यक्ष बने

मुख्यमंत्री साय, चरणदास महंत, अरुण साव और विजय शर्मा, रमन सिंह और भूपेश बघेल उन विधायकों में शामिल रहे, जिन्हें 'प्रोटेम स्पीकर' ने शपथ दिलाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सर्वसम्मति से राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित सदन का पहला सत्र मंगलवार को शुरू हुआ।

सत्र के पहले दिन आज यानी मंगलवार को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) रामविचार नेताम ने भाजपा और कांग्रेस के विधायकों तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के एक विधायक को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भूपेश बघेल उन विधायकों में शामिल रहे, जिन्हें 'प्रोटेम स्पीकर' ने शपथ दिलाई। विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समर्थन किया। विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने भी सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका भूपेश बघेल ने समर्थन किया। सिंह के

पक्ष में भाजपा सदस्यों द्वारा तीन और प्रस्ताव पेश किए गए।

सात बार विधायक रहे रमन सिंह ने 2008, 2013, 2018 और 2023 में लगातार चार बार राजनांदगांव सीट से जीत हासिल की है। 1999 में उन्हें एक बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में सिंह ने कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 45,084 मतों के अंतर से हराया था। सिंह को छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ने अपने 15 साल के लंबे राजनीतिक कार्यकाल (2003 से 2018) के दौरान एक सक्षम प्रशासक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है।

भाजपा ने पिछले माह राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में जीत के बाद सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के हाथ में राज्य की कमान सौंप दी।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने राज्य में पांच साल के अंतराल के बाद 90 में से 54 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की है, जबकि 2018 में 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस 35 सीट पर सिमट गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) एक सीट जीतने में कामयाब रही है।

मुख्यमंत्री साय ने डॉ. रमन को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सदन में दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर आज सदन में बधाई देते हुए कहा कि डॉ. सिंह प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा है। उन्हें संसदीय परंपराओ और विधि विधायी कार्यों का लम्बा अनुभव है। उनके अनुभवों का लाभ इस सदन को मिलेगा। उन्होंने डॉ.रमन सिंह की सहज, सरल और सौम्य छवि, सबको साथ लेकर चलने की विशेषता का भी उल्लेख किया। इसके पहले प्रोटेम स्पीकर श्री रामविचार नेताम ने उनके सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की सदन में घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने परंपरा के अनुसार उन्हें अध्यक्षीय आसंदी तक पहुंचाया।

सत्र के दौरान सदन में छूटे हंसी के ठहाके, बघेल बोले अब यहां दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं

रायपुर। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भूपेश जब सदन में बोलने के लिए उठे तो सदन का पूरा माहौल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि मैं सोच रहा था कि सदन में मैं ही अकेला भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। इस सदन में अब दो दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। बघेल ने कहा कि जनता ने हमे यहां बिठा दिया और आपको वहां बैठा दिया, खैर कोई बात नहीं। बघेल ने रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि पिछली सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष थे आपको बोलने का मौका ज्यादा देते थे। बघेल ने कहा कि उम्मीद है कि आप भी हमें सदन में बोलने का भरपूर मौका देंगे।

सदन में मैं अकेला भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं हूं

भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि रमन सिंह का लंबा राजनीतिक अनुभव इस सदन का रहा है उम्मीद है उनके अनुभव का लाभ हमें आगे भी मिलता रहेगा। सदन की परंपराएं जो रही हैं उन परंपराओं को आगे ले जाने का काम रमन सिंह बखूबी करेंगे। इस सदन ने कई परंपराएं भी स्थापित की हैं जिसमें सभी सदस्यों का बड़ा योगदान रहा है। रमन सिंह के नेतृत्व में हम उन परंपराओं को और आगे लेकर जाएंगे।

हम उधर थे आपने इधर कर दिया

बघेल ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम

कभी उधर बैठते थे, लेकिन आपने हमें इधर बैठने को मजबूर कर दिया। अब वहां पर विष्णुदेव साय जी आ गए हैं। जब आप इधर बैठते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे, अब हम इधर हैं और 15 की जगह 35 सीटें हैं तो हम भी जोर लगाकर आक्रमण करेंगे। हम लोगों की भूमिका बदल गई है लेकिन जनता के हित का काम हम दोनों लोगों के लिए सर्वोपरि है।

जब सदन में लगे हंसी के ठहाके

सदन में चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कुरुद से विधायक चुने गए अजय चंद्राकर ने बघेल को कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों। चंद्राकर के सवाल पर बघेल ने कहा कि अभी तो चर्चा शुरु हुई है हम कभी और इस पर चर्चा कर लेंगे।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस ने नेशनल एलायंस कमेटी का किया गठन

रायपुर। कांग्रेस ने नेशनल एलायंस कमेटी गठित की है। इस कमेटी में कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि, इस कमेटी में भूपेश बघेल के अलावा मुकुल वासनिक का नाम भी शामिल है। जिन्हें कमेटी का संयोजक बनाया गया है। अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश का नाम भी कमेटी में शामिल है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एलायंस का गठन किया है।

छगन मुंदड़ा ने सीएम साय को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष छगन लाल मुंदड़ा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा है। जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निर्माता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का विस्तार से जिक्र हो। साथ ही राज्य निर्माता के रूप में उनका चित्र सभी सरकारी कार्यालयों में लगाना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी मांगो को जल्द पूरा किया जाएगा।

साय से आईसीएआई मध्य भारत क्षेत्रीय काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से यहां

राज्य अतिथि गृह पहुना में आईसीएआई के मध्य भारत क्षेत्रीय काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) के मध्य भारत क्षेत्रीय काउंसिल द्वारा रायपुर में आयोजित किए जा रहे 43वें रीजनल कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में 23 व 24 दिसंबर को इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रण हेतु धन्यवाद दिया।

छत्तीसगढ़ के 8 वाणिज्यिक गैर कोयला खदानों की नीलामी आज

रायपुर। कोयला मंत्रालय के द्वारा 20 दिसंबर को नई दिल्ली में वाणिज्यिक गैर कोयला खदानों नीलामी करेगा जिसमें छत्तीसगढ़ की 8 खदाने भी शामिल है। आगामी दौर में कुल 26 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिसमें सीएम (एसपी) अधिनियम 2015 के तहत 3 खदानें और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत 23 खदानें शामिल हैं। इनमें से 7 कोयला खदानों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई हैं, जबकि 19 खदानों को आंशिक रूप से पहचाना गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयले के सातवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत, 5 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है, जिसमें चार सीएमएसपी कोयला खदान और एक एमएमडीआर कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें से चार पूरी तरह से पहचान ली गई हैं और एक खदान को आंशिक रूप से पहचाना गया है।

आज आप जहां बैठे हैं वो मेरा अतीत है, आज मैं यहां हूं ये मेरा वर्तमान है: महंत

■ **नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रमन सिंह को दी बधाई**

रायपुर। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का कार्यकाल मंगलवार 19 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया। पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और तीन बार के पूर्व सीएम रहे रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया। इस अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन में रमन सिंह को बधाई दी गई।

रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उनके

सम्मान में कई बातें कही। चरण दास महंत ने कहा कि आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है, आज मैं यहां हूं ये मेरा वर्तमान है। वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहेगा।

चरण दास महंत ने कहा हम सब आपके स्वभाव को जानते हैं, आप एक बेहतर इंसान हैं। छत्तीसगढ़ की अपने 15 साल तक सेवा की है। ये हम सबने देखा है आपका छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच प्रभाव प्रशंसनीय रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं यहां हूं ये मेरा वर्तमान है। वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे साथी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इधर-उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो ऐसा हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज्यादा समय इधर(विपक्ष) को दिया। इसलिए आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इस बात का ध्यान रखेंगे।

रमन सिंह के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर चरण दास महंत ने कई बातें कही हैं। महंत ने रमन सिंह से अपनी मित्रता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों सांसद थे तब हम दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी, जो सबको खटकती थी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आप संसद सदस्य से अध्यक्ष बने, तब थोड़ी दरार आने लगी। जब आप मुख्यमंत्री बने तब दरार बढ़ गई। अंत में महंत ने रमन सिंह के लिए लाइनें कही। जो हममें तुम्हें करार था। तुम्हें याद हो के ना हो।

रमन सिंह के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों की तरफ से शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं। रमन सिंह को लगातार बधाई मिल रही है। रमन सिंह लोकसभा सांसद, केंद्र में मंत्री रहे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के तीन बार सीएम रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी रमन सिंह ने संभाला है। अब रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी नई भूमिका में दिखेंगे।

25 दिसंबर को मनाया जाएगा सुशासन दिवस

■ **पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सभी जिलों जनपद और ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी**

रायपुर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 के पूर्व ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ-सफाई आवश्यक मरम्मत आदि कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन दिवस के दिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि और आम नागरिक ग्राम तथा ग्राम पंचायत में सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लेंगे। इसी क्रम में ग्राम और ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर से आगामी एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने राज्य के सभी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सुशासन दिवस के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को

आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति में प्रातः 10 बजे अटल चौक से प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर अटल चौक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्ज्वलन पश्चात् उपस्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा ग्राम तथा ग्राम पंचायत में सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने कलेक्टरों से कहा है कि सुशासन दिवस के आयोजन के लिए अपने-अपने जिलों के समस्त जनपद और ग्राम पंचायतों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किया जाए और सुशासन दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही आयोजित कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं पालन प्रतिवेदन संचालक, पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर को भेजा जाए।

हम कथा में बैठे हैं और कथा भी हममे बैठे तो वह कथा स्थल ही अयोध्या व गोकुल

आज मनुष्य का सोच गिरते जा रहा है, ठीक नहीं

रायपुर। कथा की अवहेलना कर जहां कीर्तन होंगे वह केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह जाते है। इसलिए नाम के साथ के ध्यान भी कथा के लिए जरूरी है। हम कथा में बैठे हैं और कथा भी हममे बैठे तो वह कथा स्थल ही अयोध्या व गोकुल है। श्रवणकर्ता जब यह मान ले कि कथा में जो बताया जा रहा है मेरे कल्याण के लिए हैं, जो कहा जा रहा है वह मेरे में सुधार लाने के लिए है तो कथा सार्थक हो गई।

सिंधु पैलेस शंकरनगर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सत्संग में कथा व्यास गौर दास जी महाराज ने बताया कि भक्ति तीन प्रकार की होती है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण भक्ति के पश्चात प्रगट होने वाला कीर्तन है और जो विस्मृत न हो वह स्मरण है। श्रोता कैसे हो जो गुरु के वाक्य पर भरोसा करे, गुरु भी चार प्रकार के होते है जगत गुरु साक्षात भगवान, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु। कथा में मन का लगना भी जरूरी है, मन यदि वश में हो गया मतलब मोहन भी वश में हो गया। मन को लगाने के पूर्व की कुछ भूमिका है जैसे आसन लगे, आंखे कितनी देर लगती है,कान लगते हैं कि नहीं, श्वासों की गति ये सब मन

को भटकाने के साधन है और कथा श्रवण के लिए इन पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन आज की विडंबना ही यही है कि अपने घर की देखते नहीं और दूसरों के घर का देखने चले। श्रीमद भागवत कथा में लीलाओं का वर्णन तो है ही पर शिक्षा से जुड़ी बातें भी बतायी गई है।

आज कन्याओं के जन्म पर अवहेलना झेलनी की शर्मनाक बात आती है, कन्याओं के भ्रुण हत्या की बात आती है आखिर क्यों? भागवत कथा में पूजी गई हैं कन्याएं, सुकदेव जी कन्याओं के उस वंश परम्परा की गायन कर रहे हैं जहां 16 कन्याएं पैदा हुई जिनमें 14 वें नंबर की कन्या थी आहूति जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। आज मंत्र के साथ स्वाहा करके आहूति दी जाती है। 15 वें कन्या थी स्वधा, जिसका विवाह पितरों से हुआ था। मृत्यु निमित जो भी कार्य होते हैं उसमें स्वधा का उपयोग हैं और 16 वीं कन्या सती थी जिनका विवाह शंकर जी से हुआ और बाद में पार्वती के रूप में प्रगट हुई थीं। कथा व्यास ने बताया कि हर किसी के जीवन में सुमति और कुमति है, अब ये हम पर है कि हम किसे अधिक महत्व देते हैं। मंथरा रूपी कुमति तो भगवान राम के अयोध्या में भी थी। इसलिए विचार, धारणा, मति को गंदा न होने दें। आज आर्थिक स्तर से लेकर मनुष्य का हर स्टेटस बढ़ रहा है पर सोच गिरते जा रहा है,यह ठीक बात नहीं। मानसिक स्तर को उठा सकते हैं, उठा कर रखें यही प्रयास होना चाहिए।

भूपेश बोले- हिसाब-किताब बराबर हो गया, बृजमोहन ने कहा- ये कारवां क्यों लुटा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की चुटकी ली। जहां बीजेपी ने कांग्रेस की चुटकी ली तो कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया। कुल मिलाकर पहले दिन सदन में हंसी ठिठोली देखने को मिली।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने नए विस अध्यक्ष रमन सिंह को लेकर कहा कि हम सब आपके स्वभाव को जानते हैं। आप एक बेहतर इंसान हैं। छत्तीसगढ़ की अपने 15 साल तक सेवा की है। ये हम सबने देखा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच आपका प्रभाव प्रशंसनीय रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आप जहां पर बैठें हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं यहां हूं ये मेरा वर्तमान है। वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे साथी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।। इधर-उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो,

ऐसा हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज्यादा समय इधर को (विपक्ष) दिया, इसलिए आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इस बात का ध्यान रखेंगे।

उन्होंने कहा जब हम दोनों सांसद थे तब हम दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी जो सबको खटकती थी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लग गई थी। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आप संसद सदस्य से अध्यक्ष तब थोड़ी दरार आने लगी जब आप मुख्यमंत्री बने तब दरार बढ़ गई। महंत ने रमन सिंह की तारीफ में कहा कि जो हमने तुम्हें करार था तुम्हें याद हो के ना हो।

भूपेश बघेल ने रमन सिंह को बधाई देते हुए कहा कि रमन सिंह का लंबा अनुभव, लोकसभा सदस्य, राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में रहा है। इस पवित्र सदन में कई नई परंपराओं का निर्वहन हुआ है जब रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था की मैं अकेला ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। हम दोनों की भूमिकाएं बदल गईं, इसीलिए अब हिसाब-किताब बराबर हो गया। इस दौरान रायपुर दक्षिण से बीजेपी के सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीच में चुटकी लेते हुए कहा कि तू इधर-उधर की बात ना कर, ये बता ये कारवां क्यों लुटा...।

सत्र के दूसरे दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण

20 दिसंबर को सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके बाद मंत्रियों का परिचय और सरकारी कामकाज होंगे।

अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा

शीतकालीन सत्र के आखिरी और तीसरे दिन अनुपूरक बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। मतदान और विनियोग विधेयक पर पुनर्स्थापन होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकारी काम होंगे।

ये विधानसभा जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का मैं...

भरे सदन में अनुज शर्मा ने कही ये बात

छत्तीसगढ़ विधानसभा को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह को आज विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रमन सिंह का नाम विधानसभा अध्यक्ष रखा। जिसका समर्थन उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी रमन सिंह का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए रखा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका समर्थन किया। 5 प्रस्ताव रखा गया। सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रमन सिंह को बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सहित विपक्ष को भी बधाई दे देते हुए कहा कि इन्होंने परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष केंद्र में मंत्री , सांसद विधायक और मुख्यमंत्री रहे हैं इन्हें सदन का लंबा अनुभव है। इनका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहा है आगे भी मिलता रहेगा।

संसद में फैलाये गये धुएं पर हो रही राजनीति

सुरेश हिंदुस्तानी

लोकतंत्र में सरकार की कार्यप्रणाली से सहमत या असहमत होना एक जायज प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। रचनात्मक विरोध होना लोकतंत्र को और भी अधिक मजबूत बनाने का कार्य करता है। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से कुछ लोगों ने विरोध किया, उसे लेकर कई प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं। तथ्यात्मक बात यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोपियों पर कार्यवाही के बजाय सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि यह सच भी है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए सरकार की ओर से इस मामले जिम्मेदारी वाला व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष का रवैया भी देश हित का होना चाहिए। क्योंकि नाकामी को लेकर राजनीति करना देश घातक होती है। देश के प्रति जिम्मेदारी सभी की है। यहां सुरक्षा में चूक तो है ही, पर आरोपियों का व्यवहार और तरीका भी पूरी तरह से अनुचित ही था। वर्तमान में देश की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लेना एक आम बात होती जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की मर्यादाओं को भी लांघने का कृत्य भी ज्यादा कदा दिखाई देता है। यह बात सही है कि विविधता वाले भारत देश में कोई एक बात सबको सही लगे, यह हो ही नहीं सकता, लेकिन लोकतंत्र यही कहता है कि उस बात को चाहने वाले अधिक हैं तो बड़ी खुशी के लिए छोटे दुख को तिरोहित कर देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अधिकांशत: गलत मार्ग पर ही ले जाने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर उठाया गया कदम कुछ हद तक सांत्वना दी सकता है, लेकिन जिससे अधिकांश समाज को लाभ मिलता है, वह आने वाले समय में हमारे लिए भी सकारात्मक प्रमाणित होता है। विपक्ष का रवैया आरोपियों के हौसले बढ़ाने वाला है, वे आरोपियों पर नरम और सरकार पर गर्म हो रहे हैं। हालांकि यह भी सर्वथा सत्य है कि देश की संसद पर इस प्रकार का कृत्य सरकार द्वारा प्रायोजित सुरक्षा पर भी अनेक प्रकार के सवाल स्थापित करता है। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवाल जायज हैं, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाना अत्यंत गंभीर है। विपक्षी दल के सांसद भी देश की संसद का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी भी भारत की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी कम नहीं होती। सरकार के हर कदम की आलोचना करना मात्र ही राजनीति नहीं होती। राजनीति में देश भाव दिखना चाहिए। आज देश का राजनीतिक वातावरण एक प्रकार से प्रदूषित जैसा दिखाई देता है। देश में इस राजनीतिक प्रदूषण के लिए हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है। क्योंकि आज के राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने और स्वयं को स्थापित करने की राजनीति करते दिखाई देते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की राजनीति किसी भी प्रकार से देश हितैषी नहीं कही जा सकती, लेकिन सवाल यह भी है की संसद की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए कुछ लोग असंसदीय हरकत कर देते हैं। यह घटना सरकार के सुरक्षा इंतजामों पर गहरे सवाल अंकित करती है। अगर विपक्षी दल सरकार के गृह मंत्री पर सवाल उठाते हैं तो इसमें गलत क्या है। गृह मंत्री को जवाब देना ही चाहिए। क्योंकि गृहमंत्री जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? यहां पर सवाल यह भी आता है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो क्या विपक्ष उनको सुनने को तैयार होगा? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कई बार विपक्षी दल चर्चा से भागे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इस घटना को चाहे कुछ भी रूप दिया जाए, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह सभी मोदी सरकार के विरोधी हैं। विपक्षी दल इन आरोपियों के बारे में यह वकालत करते दिखते हैं कि वह बेरोजगारी के कारण मोदी सरकार से दुखी थे, और वे सरकार के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। परंतु विपक्षी दलों को यह भी समझना चाहिए कि क्या आक्रोश व्यक्त करने का यह तरीका ठीक था? इसका प्रथम दृष्टया उत्तर यही होगा कि विरोध करने का स्थान संसद नहीं होना चाहिए। जैसे विरोध के अन्य आंदोलन होते हैं, वैसे ही लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। यहां एक सवाल यह भी आ रहा है कि जो विरोध करने वाले हैं, उनको संबल कौन दे रहा है? क्या भाजपा के वे सांसद उनको संबल दे रहे हैं, जिन्होंने उनका पास बनवाने में सहयोग किया, या फिर यह भी विरोधियों की साजिश का हिस्सा है। क्योंकि एक सांसद अपनी ही सरकार के विरोध करने वालों को इस प्रकार का कृत्य करने की अनुमति नहीं दे सकता। और अगर यह सच है तो भाजपा के लिए और भी गंभीर बात है।

नयी राजनीति और मुख्यमंत्रियों का चयन

प्रभु चावला

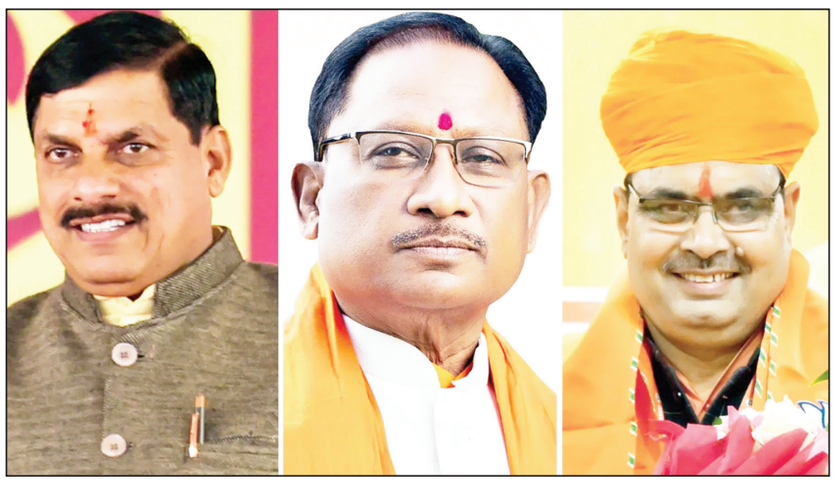

यह नयी राजनीति का प्रारंभ है। इस नये दौर की राजनीति में मीडिया के पास संदेश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संदेश, संदेशवाहक और माध्यम है। भाजपा की संस्कृति में नव सामान्य को कोई अन्य रहस्यात्मक सूत्र कैसे विश्लेषित कर सकता है, जहां राज्यों के नये नेता पूर्ण आश्चर्य की तरह हैं? कोई राजनीतिक या मीडिया विशेषज्ञ दूर-दूर तक नहीं भांप सका कि मोदी लहर की बड़ी जीत के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नये राजनीतिक सीइओ कौन बनेंगे। जब इनके नाम सामने आये, तब सैकड़ों पत्रकार नये मुख्यमंत्रियों के गुण खोजने लगे। सबने कहा कि तीनों मोदी की अभिव्यक्ति हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों- पहली बार विधायक बने राजस्थान के भजन लाल शर्मा, तीन बार के विधायक मध्य प्रदेश के मोहन यादव और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय- के चयन में जो समान कारक है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। मोदी के इस आश्चर्यजनक चयन ने टीवी पर बतकही के लिए पूरा माहौल बना दिया। विश्लेषक इन निर्णयों को जातिगत समीकरण, क्षेत्र और संघ से जुड़ाव के आधार पर देख रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। लेकिन इन नेताओं के बारे में जानने से अलग ही कहानी उभरती है।

क्या मोदी ने जातिगत राजनीति की है? बिल्कुल नहीं। अद्भुत अनपेक्षित मतैक्य के तत्व के साथ-साथ पुराने नेताओं की जगह नये चेहरों की मोदी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णु देव साय का चयन पर आदिवासी क्षेत्र में भाजपा को मिले बड़े समर्थन का प्रभाव रहा। प्रधानमंत्री को आशा है कि यह समर्थन 2024 में भी बना रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 17 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। साल 2018 में उसे केवल तीन सीटें मिली थीं। राज्य में 15 साल शासन चलाने वाले कद्दावर नेता रमन सिंह के बाद उनकी जगह लेने वाला साय के अलावा कोई और नहीं था। साय पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष, तीन बार विधायक तथा एक बार सांसद रहे हैं। राजस्थान में जाति से ब्राह्मण भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री की पसंद हैं। चूंकि राज्य भाजपा में बहुत गुटबाजी है, इसलिए मोदी ने स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुना है। उन्होंने ताकतवर गुर्जर, मीणा और जाट नेताओं, जिनके पास जीती गयीं 115 सीटों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा है, के दावों की अनदेखी कर सोचा-समझा जोखिम उठाया। मध्य प्रदेश में तीन बार के विधायक मोहन यादव गुटबाजी से परे हैं और जब स्थानीय नेता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे थे, तब वे धैर्य के साथ खड़े थे। इसी कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अगले साल के चुनाव में संख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश में यादव और राजस्थान में ब्राह्मण कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं हैं।

इन तीन नेताओं में जो समान कारक है, वह है उनकी ठोस हिंदुत्व पृष्ठभूमि। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा संघ के जरिये शुरू की थी। उपमुख्यमंत्रियों के लिए मोदी के चयन में भी जाति महज संयोग की बात रही। छह नये खिलाड़ियों में केवल दो ब्राह्मण हैं- मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल और छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा। शेष चार विभिन्न समुदायों से हैं। ये चयन जाति की बाधाओं को तोड़ने या उन्हें कमजोर करने के मोदी के दर्शन के विस्तार हैं। यह प्रक्रिया महाराष्ट्र और हरियाणा से शुरू हुई थी। नागपुर के युवा ब्राह्मण देवेंद्र फड़नवीस को मराठा-बहुल महाराष्ट्र के लिए चुना गया था। हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर के रूप में पहला पंजाबी संघ प्रचारक मुख्यमंत्री मिला। तब वे पहली बार विधायक बने थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चयन अंतिम समय में हुआ था। तब वे विधायक भी नहीं थे। जब आनंदीबेन पटेल को अहमदाबाद से राज्यपाल बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया, तब उनकी जगह कोई पटेल मुख्यमंत्री नहीं बना, बल्कि एक जैन विजय रुपाणी को चुना गया। अभी भाजपा के 12 मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य के जातिगत समीकरणों का आभास नहीं होता। एक ब्राह्मण, दो अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जनजाति से है। शेष उच्च जातियों से हैं। कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में मोदी को वोट दिया।

जैसे नयी पीढ़ी का चयन हो रहा है, वह उस भविष्य का सूचक है, जहां भाजपा आलाकमान को स्थानीय नेताओं से क्षेत्रीय स्तर पर केसरिया दूत बनने तथा बिना शर्त संघ के एजेंडे को आगे ले जाने की अपेक्षा होगी। यह भी इससे इंगित होता है कि मुख्यमंत्री के चयन में राज्य के नेताओं की भूमिका अत्यंत न्यून है। पुरानी भाजपा में पर्यवेक्षकों की राय के आधार पर संसदीय बोर्ड निर्णय लेता था। इस बार ऐसी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। पर्यवेक्षक सीलबंद लिफाफा लेकर गये थे, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा चुना हुआ नाम था। उसे अंतिम क्षण में खोला गया। विधायक दल की बैठक से पहले ही यादव का नाम टीवी पर घोषित हुआ। किसी भी रिपोर्टर को भनक तक नहीं थी कि बैठक में क्या हो रहा है। मोदी ने अपने बड़े समर्थकों- खट्टर, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा- को पर्यवेक्षक बनाया, जो न तो मीडिया में छाये रहने की ललक रखते हैं और न ही लुटियन दिल्ली के बौनों के साथ उठते-बैठते हैं। आदिवासी नेता मुंडा को एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए भेजा गया, तो खट्टर का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान जैसे सफल एवं लोकप्रिय नेता की भावनाओं को शांत करना था। वरिष्ठ राजपूत और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह को ठाकुर और रजवाड़ा वर्चस्व वाले राज्य में एक नये चेहरे को पदस्थापित करने का कार्यभार दिया गया। नये चेहरों से 2024 में मदद मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। पिछले दोनों आम चुनाव राज्य के क्षत्रपों ने नहीं जीते थे, बल्कि जीत नरेंद्र मोदी के दमदार करिश्मे का नतीजा थी। उन्हें राम ने राजमुकुट दिया है और राम भक्ति उनका रथ चलाती है। वे अपने नये साथियों के लिए अल्फा और ओमेगा दोनों है तथा राम में आस्था उन्हें परस्पर जोड़ती है। साल 2018 में भाजपा तीनों राज्यों में हार गयी थी, फिर भी 2019 में मोदी ने 65 में 62 सीटें जीतीं। राज्य के मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी मजबूत राज्य और मजबूत केंद्र को एकजुट करती है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' सुनिश्चित करने के लिए मोदी का एजेंडा है- 'एक देश, एक नेता।' अपने दांवों से प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि वे पार्टी के मुख्य संरक्षक भी हैं और उसके रणनीतिक मानसिक संचालक भी।

कृपया इनसे सीखें

पढ़ाई की जिद से उम्र को हरा दिया

एम चेलाताई

गुणे अच्छी तरह कॉलेज में दाखिले का मेरा आवेदन पत्र फाड़ दिया था। माध्यामिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करके मैंने अपने सपने जीने का दुस्साहस किय पूरी कर उस वक्त परिवार और समाज में लड़कियों को इसकी अनुमति नहीं थी। है पढ़ाई के लिए पेन्नई जाना चाहती थी, पर मेरे पिता ने मेरी एक न सुनी। पा छूटी, तो किसी भी दूसरी आम भारतीय लड़की की तरह घर से कुछ किलोमी दूरी पर स्थित पड़ोस के एक गाँव में मेरी शादी कर दी गई। वैसे तो शादी को पाटना, पढ़ाई को लेकर मेरी बची-खुची उम्मीदों पर पानी फिरने सरीखो थी पा मुझे अपने पति से थोड़ी-बहुत अपेक्षा थी कि शायद वह मेरी इच्छाओं की कद करें। लेकिन नहीं, मेरे पति का रवैया भी पिता की सोच से जुदा नहीं था। द्विग हासिल करने की मंजिल हर बीतते वक्त के साथ मुझसे दूर होती दिख रही थी।

साल-दरअसल बीतते गए। मेरी जिंदगी हर दिन घर में कैद होकर घुट रही थी। एक दिन मेरे पिता गुजर गए। वह एक सरकारी मुलाजिम थे। नौकरी के दौरान हुई उनकी मौत की वजह से उनके विभाग की ओर से मुझे नौकरी करने का प्रस्ताव मिला। गनीमत रही कि शुरुआती आनाकानी के बाद मेरे पति ने मुझे गोपालपुरम के तमिलनाडु आपूर्ति निगम में लिपिक की नौकरी करने की अनुमति दे दी। मैं भले ही घर की चौखट से बाहर निकलकर काम करने लगी थी, पर अब भी पढ़ाई न पूरी कर पाने की कसक मन में ही थी। हमेशा यही लगता कि मैं डिग्री की योग्यता रखती हूँ। मैंने दोबारा कोशिश की। लेकिन एक बार फिर मेरे पति मेरे प्रयासों के आड़े आ गए और मुझे अनुमति नहीं मिली।

मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती थी, पर अपनी पढ़ाई की इच्छा को मारना भी मेरे लिए आसान नहीं था। विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने के लिए एक कोर्स में शामिल होने को मेरी रिटायरमेंट तक बाकी रही। मैं 2009 में रिटायर हो गई, लेकिन तब तक मेरा सपना अधूरा ही रहा। मैं खुद तो नहीं पड़ सकी, मैंने अपनी बेटियों को तब तक पढ़ने दिया, जब तक उनकी इच्छा थी। चार साल पहले मेरे पति भी चल बसे। उनके जाने के बाद यों ही मुझे एक बार फिर पढ़ाई पूरी करके अपना सपना साकार करने का ख्याल आया। फिर क्या, मैंने अपनी बेटियों से सलाह ली और उनकी मदद से जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने सपने को पूरा करने में जुट गइ।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-16)

गतांक से आगे...

तैलधारवत् अविच्छिन्न, घण्टा के गम्भीर स्वर की तरह प्रणव (ओंकार) की ध्वनि वाला अनाहत नाद होता है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग (मूल) प्रकाशमय और वाणी से परे है, इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद् है।

दोनों नेत्रों के बीच जाग्रत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। स कार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वं का स्वरूप है। ह कार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत पद के रूप में है। जो भी प्राणी स कार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से ह कार रूप हो जाता है। यही सोऽहम् और तत्त्वमसि की साधना है।

[ऋषि यहाँ सोऽहम और तत् त्वम बोध वाक्यों की समानता एकरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। साधक जब तात्त्विक दृष्टि से स्व की ओर देखता है, तो सोऽहमस्मि का बोध करता है तथा जब बाहर की ओर उसी दृष्टि से देखता है, तो तत्त्वमसि का अनुभव करता है।]

जीव को इन्द्रियाँ बन्धन में बाँधती हैं, आत्मा को इन्द्रियाँ नहीं बाँध सकती हैं। जब तक ममता होती है, वह जीव रहता है, ममता के बन्धन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है।

सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवता एवं भू: भुव: स्व: लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं, वह परम प्रकाशरूप ओंकार है। परम प्रकाशमान ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियाँ विराजमान हैं। सदैव वाणी से उसका जप करे तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप करते हुए उसी परमप्रकाशरूप ओंकार में स्थिर हो जाए।

क्रमश: ...

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस

अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच एकजुटता के महत्त्व को बताने के लिए, गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस को विश्व एकजुटता कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। एक व्यक्ति या तो शिक्षा में योगदान देकर या गरीबों या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करके दिन में भाग ले सकता है या मना सकता है। इसके माध्यम से सरकारों को

सतत विकास लक्ष्य के गरीबी और अन्य सामाजिक बाधाओं का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मानव एकजुटता का अर्थ, साझा लक्ष्यों और हितों के बारे में जागरूकता है जो एकता की मनोवैज्ञानिक भावना देता है और समाज में संबंधों को मजबूत करता है और लोगों को एक साथ बांधता है। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम डिक्लेरेशन में कहा गया है कि एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

एकजुटता के महत्व पर जन जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तरीकों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है।

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया में, विशेष रूप से विकासशील देशों में सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को एक संकल्प पारित कर के एकता को मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों में से एक के रूप में पहचान दी थी। उस संकल्प के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाने की घोषणा की।

इसी के साथ यूएनओ द्वारा गरीबी मिटाने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की घोषणा करके एकजुटता की अवधारणा को और बढ़ावा दिया गया।

यह एक बेहद महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के देशों और लोगों को एक साथ लाने के प्रयास किए जाते है।

यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास एजेंडा लोगों पर केंद्रित है, जो लोगों को गरीबी, भूखमरी और बीमारी से बाहर निकालने के लिए निर्धारित वैश्विक साझेदारी द्वारा समर्थित है, ठीक उसी तरह वैश्विक साझेदारी की नींव पर ही वैश्विक सहयोग और एकजुटता का निर्माण किया जा सकता है।

मोदी का महाअभियान, क्या है बनारस का तमिल कनेक्शन?

अभिनय आकाश

काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं। इसलिए देश-दुनिया के लोग इस तीर्थ स्थान पर एक बार जरूर आना चाहते हैं। लोग भगवान शिव की इस नगरी वाराणसी के साथ ज्ञान और अध्यात्म का जुड़ाव महसूस करते हैं। वाराणसी के साथ तमिलनाडु का ऐसा ही रिश्ता है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को फिर से तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने काशी-तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी भाषा के सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष को एक दूसरे से परिचित कराना है। पिछले साल पहली बार आयोजित काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाना है। इससे पहले मोदी सरकार ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 में किया था। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को इस कार्यक्रम में खुद भी हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब महादेव के एक घर से दूसरे घर तक आना है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरै मीनाक्षी के स्थान से काशी विशालाक्षी के स्थान तक आना। हम काशी और तमिलकम के बीच प्राचीन संबंध पर एक नजर डालते हैं।

काशी और तमिलनाडु के बीच दसवीं शताब्दी से ही संबंध रहे हैं। चोल काल के समय के शिलालेखों में भी वाराणसी का जिक्र है। तमिलनाडु में कई जगहों पर काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर मौजूद हैं। तमिलनाडु में काशी नाम का शहर भी है। काशी में तमिल लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हैं। आज भी काशी के लोग धार्मिक कारणों से रामेश्वरम जाते हैं और दक्षिण भारतीय लोग काशी आते हैं। 17वीं शताब्दी में शैव कवि कुमारागुरूपरार तमिलनाडु से काशी गए और वहां मठ स्थापित किया। ये मठ बाद में थानजावुर जिले में आ गए लेकिन लोग उसे आज भी काशई मठ ही कहते हैं।

किंवदंती है कि 15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र के शासक राजा पराक्रम पंड्या भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने मंदिर के लिए लिंगम वापस लाने के लिए काशी तक की यात्रा की। लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की, तो लिंगम ले जाने वाली गाय ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। पराक्रम पंड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और वहां लिंगम स्थापित किया, वह स्थान जिसे आज शिवकाशी के नाम से जाना जाता है। जो श्रद्धालु काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिए पांड्यों ने दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु में आज के तेनकासी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के डॉ विनय कुमार ने कहा कि काशी और तमिल क्षेत्र के बीच संबंध गहरा और पुराना है। डॉ. कुमार ने कहा कि बहुत बाद में, एक अन्य राजा, अधिवीर राम पांडियन ने काशी की तीर्थयात्रा से लौटने के बाद, 19वीं शताब्दी में तेनकासी में एक और शिव मंदिर का निर्माण कराया। थूथुकुडी जिले के संत कुमार गुरुपारा ने वाराणसी में केदारघाट और विश्वेश्वरलिंगम के अभिषेक के लिए जगह पाने के लिए काशी रियासत के साथ बातचीत की थी। उन्होंने काशी कलांबगम की भी रचना की, जो काशी पर व्याकरण कविताओं का एक संग्रह है।

इस वर्ष तमिलनाडु और पुडुचेरी के लगभग 1,400 गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए वाराणसी का दौरा करेंगे और कई सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रदर्शनियों में भाग लेंगे, जिसमें तमिलनाडु और वाराणसी की कला, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। तमिल प्रतिनिधिमंडल का पहला जत्था, जिसमें तमिलनाडु के छात्रों का एक समूह शामिल है, 15 दिवसीय संगमम में भाग लेने के लिए रविवार को वाराणसी पहुंचा। शिक्षकों, पेशेवरों, आध्यात्मिक नेताओं, किसानों और कारीगरों, लेखकों, व्यापारियों और व्यापारियों के छह और समूहों का भी शहर में आगमन निर्धारित है। पिछले साल के आयोजन में, तमिलनाडु के लगभग 2,400 लोगों को समूहों में वाराणसी ले जाया गया था, जो आठ दिनों तक चली और इसमें एक गहन स्थानीय अनुभव के अलावा, अयोध्या और प्रयागराज की यात्राएं भी शामिल थीं। कार्यक्रम के आधिकारिक नोट में कहा गया है कि व्यापक उद्देश्य (उत्तर और दक्षिण के) दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ पैदा करना और क्षेत्रों के बीच लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना है। संगमम का प्रस्ताव करने वाले शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष, शिक्षाविद् चामू कृष्ण शास्त्री ने 2022 में कहा था कि प्राचीन काल से, विद्वान द्वारा काशी की यात्रा के बिना दक्षिणी भारत में उच्च शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती थी। शास्त्री ने केले और कांचीपुरम से रेशम की साड़ियों और वस्त्रों का कारोबार करने वाले व्यापारियों और वास्तुशिल्प, पाककला और अन्य प्रकार के संबंधों का भी उल्लेख किया।

आज का इतिहास

1957 20 दिसंबर, बोइंग 707 की पहली उड़ान, पहला व्यावसायिक रूप से असफल जेट विमान, हुई।
1968 ज़ोलिएक किलर ने कैलिफोर्निया के वैलेजो में अपने पांच पुष्टिकर्मियों की पहली हत्या कर दी, एक मामला जो अनसुलझा है।
1973 स्पेन के प्रधानमंत्री एडमिरल लुईस ब्लांको मेड्रिड में कार बम विस्फोट में मारे गए।
1985 तिरूपति बालाजी मंदिर में भगवान वैंकटेश्वर को 5.2 करोड रूपये की कीमत वाला हीरा जडित मुकुट चढाया गया।
1988 अवैध ड्रग्स के धंधे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध को नियंत्रित करने वाले गैर-सरकारी ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वियना में हस्ताक्षर किए गए थे।
1989 अमेरिकी बलों ने पनामा पर हमला करने के लिए मैनहेम नोरिएगा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण किया।
1993 डोनाल्ड ट्रम्प ने मारला मैपल को उतारा।
1995 पॉल रोएबसन लॉन्गाकेयर थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में 14 प्रदर्शनों के लिए खुलता है।
1995 बोस्नियाई युद्ध को समाप्त करने वाले डेटन समझौते के अनुसार, नाटो के नेतृत्व वाले आईएफओआर ने बोस्निया और हर्जेगोविना में शांति अभियान शुरू किया।
1999 पुर्तगाल ने मकाऊ की संप्रभुता हस्तांतरित कर दी, जिसे उसने 16 वीं शताब्दी के मध्य से चीन को सौंप दिया था।
1999 पुर्तगाल ने मकाओ क्षेत्र को चीन को सौंपा।
2007 पाब्लो पिकासो के पोर्ट्रेट ऑफ़ सुज़ैन ब्लोच को एसओएओ पाउलो म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट से चुराया गया था।
2007 पाकिस्तान की संघीय शरीयत अदालत ने पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया।
2009 नाइजीरिया के कोगी राज्य के एक बाजार में एक भगोड़े ट्रक से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।

आखिर इतनी आसानी से कैसे मान गईं वसुंधरा राजे?

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के पद पर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा का चयन हो चुका है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की व जयपुर राजघराने की दीया कुमारी तथा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही राजस्थान में विधिवत रूप से भाजपा की सरकार काम करने लग गयी है। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी का नाम तय कर दिया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका भी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चयन हो जाएगा। राजस्थान में भाजपा के 115 विधायक जीत कर आए हैं। इसके साथ ही कई निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में भाजपा के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पांच साल तक सरकार चलाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है।

भजनलाल शर्मा के नेता पद के चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषक आशंका जता रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद के अलावा किसी अन्य के नाम पर सहमत नहीं होंगी। विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वसुंधरा राजे द्वारा अपने आवास पर विधायकों को बुलाकर लगातार शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था। मगर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर जयपुर आए तो उन्होंने मात्र दो घंटों में ही भजनलाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर वसुंधरा राजे के पूरे खेल को ही बिगाड़ कर रख दिया था। इतना ही नहीं भजनलाल के नाम का प्रस्ताव भी वसुंधरा राजे से ही करवाया गया था। विधायक दल की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर वसुंधरा को दी थी। जिस पर भजनलाल शर्मा का नाम लिखा था। राजनाथ सिंह द्वारा दी गयी पर्ची पर लिखे नाम को पढ़कर एक बार तो वसुंधरा सकपका गयी थीं। मगर बाद में उन्होने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव कर दिया था।

लोगों का कहना है कि नेता पद के चयन से पहले वसुंधरा राजे व उनके समर्थक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल जैसे कई नेता व विधायक लगातार कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जैसी अनुभवी को ही प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का सामना वसुंधरा राजे जैसी अनुभवी नेता ही कर सकती हैं। उनको

दो बार सरकार चलाने का अनुभव है। वह पूरे प्रदेश से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मगर वसुंधरा राजे के किसी भी समर्थक की एक भी नहीं सुनी गई और भजनलाल के नाम की घोषणा हो गई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जब जयपुर में वसुंधरा राजे विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रही थीं। तब उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह पर भी जयपुर के एक होटल में कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी करने की खबरें आई थीं। तब भाजपा आलाकमान सतर्क हो गया और वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व गृहमंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे को दो टूक शब्दों में समझा दिया था कि इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। पार्टी नए लोगों को आगे करेगी ऐसे में आपको पार्टी का साथ देना चाहिए। चर्चा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा व अमित शाह ने वसुंधरा राजे को कड़ाई से कह दिया था कि वह एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुकी हैं। इसलिए अब उनको विश्राम करना चाहिए। यदि वह पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगी तो उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा।

चर्चा है कि अपने पुत्र दुष्यंत सिंह जो झालावाड़ सीट से चौथी बार सांसद हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर वसुंधरा राजे ने पार्टी आलाकमान के निर्णय के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी और उन्होंने चुपचाप पार्टी के निर्देशों का पालन किया। वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चार बार के सांसद हैं तथा आगे उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। बहरहाल वसुंधरा राजे ने तो अपने पुत्र के मोह में पार्टी नेतृत्व के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। मगर उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर बारां अंता के विधायक कंवरलाल मीणा, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी, बहादुर सिंह कोली जैसे लोग खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे उनकी छवि जरूर पार्टी नेतृत्व के सामने दागदार हुई है। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें पार्टी द्वारा सरकार या संगठन में कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी जाए। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ही वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करते समय सचिवालय जाकर उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए फोटो भी खिंचवा कर आईं और ऑल इस वेल का सन्देश देने का प्रयास किया। वसुंधरा इतना सब अपने पुत्र कि खातिर ही कर रही हैं। वरना उनकी विद्रोही छवि व लड़ाकू स्वभाव से हर कोई वाफिक है।

अब पार्टी ने भी उनके स्थान पर राजपूत नेता के तौर पर जयपुर राजघराने की दीया कुमारी को उपमुख्यमंत्री बना कर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ा दिया है। दीया कुमारी उनकी तरह बड़े राजपरिवार की बेटी के साथ महिला भी हैं। दीया कुमारी राजसमंद से सांसद व दूसरी बार विधायक बनी हैं। उन्होंने विद्याधर नगर सीट पर राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। दूसरा उपमुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया हैं। जो वसुंधरा गुट के माने जाते थे। मगर अब बैरवा सरकार में शामिल हो गये हैं। इसी तरह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वसुंधरा के साथ रहने वाले विधायक भी अब एक-एक कर खिसकने लगे हैं। वसुंधरा राजे स्वयं इस समय पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा में जिस तरह से आलाकमान प्रभावी है। उसको देखकर नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे को आगे चलकर पार्टी में कोई और अधिक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मौजूदा संकेतों से तो वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य गुमनामी की ओर ही जाता दिख रहा है। उनके कई समर्थकों का इस बार टिकट भी काट दिया गया। मौजूदा हालात को देखकर तो लगता है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे के अन्य समर्थकों को भी पार्टी में प्रभावहीन कर दिया जाये तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल, राजस्थान में जहां हर बार सरकार बदलने की परंपरा इस बार भी कायम रही है। वहीं एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला टूट गया है। भाजपा ने वसुंधरा राजे के स्थान पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनकर पुरानी परंपराओं को समाप्त कर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। यह कितनी सफल रहेगी इसका पता तो आने वाले समय में ही चल पाएगा।

भाजपा के वीआरएस प्लान से पार्टी नेताओं में हड़कंप

नीरज कुमार दुबे

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राज्यों में भाजपा का जो नया नेतृत्व तैयार किया था उसमें गुजरात में नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह और गोवा में मनोहर पर्रिकर ने पार्टी को मजबूत किया और राज्य सरकार का लंबे समय तक नेतृत्व भी किया। मोदी 2014 में गुजरात से निकल कर केंद्र की राजनीति में आ गये और प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अमित शाह के साथ मिलकर राज्यों में नया नेतृत्व खड़ा करने का काम शुरू किया। मोदी-शाह की जोड़ी ने अब तक जिन लोगों को नेतृत्व सौंपा उसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, गोवा में प्रमोद सावंत, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर में एन. बिरेन सिंह, त्रिपुरा में माणिक साहा और असम में हिमंत बिस्व सरमा ही सफल रहे और इन नेताओं की बदौलत भाजपा दोबारा राज्य की सत्ता में आ सकी। हालांकि असम में भाजपा ने विधानसभा चुनावों में किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया था लेकिन राज्य में पार्टी की सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि मोदी-शाह की जोड़ी को सिर्फ सफलता ही मिली है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, झारखंड में रघुबर दास, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत तथा हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर व त्रिपुरा में बिप्लब देव जैसे उनके प्रयोग असफल भी रहे हैं। मोदी-शाह की जोड़ी एक तरफ भारत को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के संकल्प को सिद्ध करने पर काम कर रही है तो दूसरी ओर पार्टी स्तर पर कड़े और बड़े निर्णय लेकर यह भी सुनिश्चित कर रही है कि भाजपा का राज केंद्र और राज्यों में लंबे समय तक बना रहे। मोदी-शाह की जोड़ी जानती है कि जनता परिवर्तन चाहती है। यह जोड़ी जानती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रति उपजा जनता का गुस्सा पूरी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है इसलिए समय पर कदम उठा लिया जाता है। इसके लिए कभी केंद्र में बड़े-बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाती है तो कभी राज्यों में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है तो कभी किसी राज्य में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अगले चुनावों में टिकट काट कर एकदम नये चेहरों को मौका दिया जाता है। इस क्रम में मोदी-शाह की जोड़ी ने जो नया फैसला लिया है उसके तहत अटल-आडवाणी की जोड़ी की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैयार किये गये तीन बड़े नेताओं- शिवराज सिंह चौहान, डॉ. रमन सिंह और वसुंधरा राजे को ऐसे वक्त घर बैठा दिया है जब इन तीनों ही राज्यों में भाजपा ने शानदार चुनावी जीत हासिल की है। इन तीनों ही राज्यों में नये मुख्यमंत्री का नाम सुन कर अन्य लोग तो क्या खुद वह भी चौंक गये थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखा जाये तो वसुंधरा-रमन और शिवराज का मुख्यमंत्री के रूप में कॅरियर समाप्त होना बड़ी राजनीतिक घटना है। सवाल उठता है कि वसुंधरा-रमन-शिवराज जिन्हें आजकल वीआरएस कह कर संबोधित किया जा रहा है, उन्हें राज्य में सत्ता के शीर्ष पद से वीआरएस क्यों दे दिया गया? सवाल यह भी उठता है कि मोदी और शाह की जोड़ी क्या राज्यों के बाद अब केंद्र के नेताओं को भी वीआरएस देने की तैयारी में है? सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह हाल के विधानसभा चुनावों में कई सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया क्या उसी तरह विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? सवाल कई हैं लेकिन जवाब मोदी-शाह ही जानते हैं। जहां तक शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य की बात है तो डॉ. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बना कर उन्हें राज्य की राजनीति में ऐसी भूमिका दी गयी है जिसमें उन्हें सक्रिय राजनीति से वास्ता नहीं रखते हुए सदन के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निवर्हन भर करना है।

आदिवासी नेता साय पर ही भाजपा ने क्यों लगाया दांव?

अंकित सिंह

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आदिवासी नेता विष्णु देव साय पर बड़ा दांव लगाया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं विष्णु देव साय वह आदमी है जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी अगले 5 सालों तक रहने वाली है। साथ ही साथ उनपर 2024 में पार्टी को प्रचंड विजय दिलाने की भी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि, छत्तीसगढ़ में कई बड़े नाम थे जिन पर दांव लगाया जा सकता था। लेकिन विष्णु देव साय पर ही आलाकमान ने अपनी मुहर लगाई है। लेकिन ऐसा क्यों? हम आपको वह बातें बता रहे हैं जो विष्णु देव साय के पक्ष में गया। विष्णु देव साय प्रमुख आदिवासी नेता हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी निर्णायक भूमिका में होती हैं। राज्य की 32 फ़ीसदी आबादी आदिवासी हैं और 29 सीटे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन 29 सीटों में से भाजपा ने 17 पर जीत हासिल की है। यही कारण है कि पहले भी माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। विष्णु देव साय की बात करें तो कहीं ना कहीं वह साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। लंबे समय से सियासत में रहने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं है। वे पूरी तरीके से जमीन से जुड़े हुए नेता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। विष्णु देव साय को आगे कर भाजपा ने संदेश देने की कोशिश की है कि वह ईमानदार नेताओं को आगे करती है। साथ ही साथ उन नेताओं को ऊपर के पदों तक पहुंचती है जिनकी छवि साफ सुथरी है। विष्णु देव साय संघ के भी करीबी हैं और साथ ही साथ संगठन में भी काम करने का अनुभव रखते हैं। इसका उन्हें फायदा मिला। भाजपा को ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जिसका संगठन में भी अनुभव हो और संघ में भी पकड़ हो। विष्णु देव साय ने वह कमी पूरी की। विष्णु देव साय आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में आदिवासी बहुल सीटों पर वह पार्टी को बढ़त भी दिला सकते हैं। पार्टी छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और ओडिसा के आदिवासी बहुत सीटों पर भी नजर रख रही है। ऐसे में विष्णु देव साय का इस्तेमाल पर पार्टी आदिवासी बहुल सीटों पर काम कर सकती है और चुनाव में इसका फायदा भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई बड़े दावेदार थे। रमन सिंह के अलावा जो सबसे अनुभवी चेहरा था वह विष्णु देव साय का था। जिस तरीके से भाजपा ने वादे किए हैं उसे 2024 से पहले पूरा करना भी होगा या उसकी शुरुआत करनी होगी। यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। विष्णु देव साय केंद्र में मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का अनुभव भी रहा है। यही कारण है कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है।

आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम मुहर

अभिनय आकाश

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को कायम रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थाई प्रावधान भी बताया। संवैधानिक रूप से भारत की शासन संरचना अर्ध-संघीय है। इससे इतर एकात्मक व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित होती है। भारतीय संदर्भ में जबकि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। संविधान कुछ क्षेत्रों में केंद्र की ओर झुकता है, इस प्रकार इसे अर्ध-संघीय बनाता है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ शामिल हैं जो उन विषयों को निर्धारित करती हैं जिन पर केंद्र और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में शामिल लोगों के लिए जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून लागू होगा। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा तो खत्म हो गया। लेकिन कुछ राज्य अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष प्रावधान मिलता है।

इस अर्ध-संघीय संरचना में भी सभी राज्य समान नहीं हैं। भारत की बहुलता के लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है और संविधान राजकोषीय, राजनीतिक और प्रशासनिक से लेकर विभिन्न कारकों के आधार पर राज्यों के लिए विभेदित समानता प्रदान करता है। हालाँकि, असममित संघवाद के ख़िलाफ़ एक तर्क दिया जाता है कि तथाकथित विशेष स्थितियाँ क्षेत्रवाद और अलगाववाद के बीज बोती हैं और यह राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती हैं। जबकि अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ भारत के संबंधों को औपचारिक रूप दिया, को भारत में असममित संघवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरण माना जाता

है, वहीं कई अन्य राज्य भी हैं जो अलग-अलग डिग्री की स्वायत्तता और केंद्र के साथ संबंध का आनंद लेते हैं।

अनुच्छेद 370 के ठीक बाद संविधान अनुच्छेद 371ए-1 से कम से कम नौ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाता है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की ये जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाडा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र व कच्छ के इलाके के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। इन बोर्डों का काम इन इलाकों के विकास के लिए समान राजस्व का वितरण होगा। साथ ही राज्य सरकार के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा और रोगजार के मौके प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन बोर्ड के ऊपर ही होगी। उदाहरण के लिए, नागालैंड और मिजोरम को बातचीत के आधार पर स्वायत्तता प्राप्त है, जो भारत और नागा और मिजोरम स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच एक राजनीतिक समझौता था। इसके तहत, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागाओं और मिज़ोस की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, या उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप करती हो। अनुच्छेद 371 ए को संविधान में 13वें संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था।

1986 में किए गए संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371 जी को जोड़ा गया था। इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति-रीविजों, उनके प्रशासन और न्याय के तीरकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। जम्मू-कश्मीर के मामले में केंद्र के 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि विशेष प्रावधान राज्य के लिए आंतरिक संप्रभुता का एक तत्व देता है जिसे एकतरफा नहीं छीना जा सकता है। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 12 दिसंबर को फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 केवल असममित संघवाद की एक विशेषता है, जो आंतरिक संप्रभुता के समान नहीं है।

राजनीतिक आवश्यकताओं के अलावा अन्य कारणों से भी राज्यों को रियायतें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली को लीजिए। अनुच्छेद 239एए राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए एक अनूठी व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह संविधान की पहली अनुसूची के तहत एक राज्य नहीं है, फिर भी सातवीं अनुसूची में राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। 239 एए(7) के मुताबिक संसद से बने कानून के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यकारी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, हम तदनुसार निम्नलिखित प्रश्नों को संविधान पीठ के पास भेजते हैं- पहला प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? और दूसरा क्या संसद अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है? अनुच्छेद-239एए यह भी कहता है कि इसके तहत बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद-368 के उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उक्त कानून में कोई ऐसा प्रावधान शामिल हो, जो संविधान में संशोधन करता हो या संशोधन करने का प्रभाव रखता हो।

मायावती ने भतीजे आकाश के नाजुक कंधों पर क्यों डाल दिया हाथी का भार?

डॉ. आशीष वशिष्ठ

आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे हैं। बसपा प्रमुख ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। अपनी स्थापना के 39 वर्ष की यात्रा में बसपा राजनीतिक हैसियत के हिसाब से काफी बुरे दौर से गुजर रही है। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बात करने वाली मायावती ने कभी अपने भाई आनंद कुमार को तरजीह नहीं दी। लेकिन, विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया।

बसपा प्रमुख 2017 में सहारनपुर की हुई रैली में आकाश आनंद को अपने साथ मंच पर लाई थीं। इसे आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग मंच भी कहा जाता है। इसके बाद से ही उन्हें मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। अब आकाश को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करके 28 वर्ष के आकाश के नाजुक कंधों पर हाथी जितना भारी वजन रख दिया है। बसपा से जुड़ने के बाद आकाश आनंद वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे हैं। हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश को राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर बनाने के बाद पहली बार चुनावों में पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मायावती ने भी सभी राज्यों में रैलियां कीं। कोशिश यह थी कि अगर यहां बेहतर प्रदर्शन होता है तो इसका श्रेय आकाश को ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हालिया पांच राज्यों के चुनाव में भी मिजोरम में तो बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलगांना में पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। पिछले चुनाव के मुकाबले चारों राज्यों में बसपा की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों घटे हैं। राजस्थान और एमपी के शुरुआती रुझानों में बसपा कुछ सीटों पर टक्कर देती दिखी, लेकिन राजस्थान को छोड़कर कहीं खाता नहीं खोल सकी। राजस्थान में उसे दो सीटों पर जीत मिली है। बसपा ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूरा जोर लगाया। पार्टी की मंशा यह थी कि इन राज्यों में अगर पहले जैसा या उससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। भविष्य में चुनाव बाद गठबंधन बनता है तो उसमें भी वह जोड़-तोड़ की स्थिति में आ सकती है। नतीजों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दो राज्यों-छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। राजस्थान और तेलंगाना में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर सकी।

बसपा संस्थापक कांशीराम ने अस्सी के दशक में दलित समुदाय के बीच ऐसी राजनीतिक चेतना जगाई कि यूपी में बसपा की 4 बार सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री रहीं। यूपी से सटे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी बसपा अपनी जड़ें जमाने में सफल रही थी। भले ही यूपी की तरह देश के दूसरे राज्यों में बसपा की सरकार न बनी हो, लेकिन विधायक और सांसद जीतते रहे हैं।

दरअसल, कांशीराम के निधन के बाद से दलित और पिछड़ी जातियों का बसपा से लगातार मोहभंग होता चला गया। मायावती के हाथों में बसपा की कमान आने के बाद पार्टी ने 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन जातीय क्षत्रपों के धीरे-धीरे बसपा से निकलने और निकाले जाने के बाद पार्टी कमजोर होती चली गई।

देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बसपा का ग्राफ चुनाव-दर-चुनाव गिर रहा है। यूपी में बीएसपी को 2017 में 19 सीटें मिली थीं और तब उनका वोट प्रतिशत 22.20 था। साल 2012 में बीएसपी को 80 सीटें और 25.90 फीसदी वोट मिले। जबकि, 2007 में 206 सीटों के साथ 30.40 फीसदी वोट हासिल हुए और 2002 में 98 सीटें और 23.10 फीसदी वोट मिले थे। लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई और पार्टी को 13 फीसदी से भी कम वोट मिले हैं। जबकि, 1996 से लेकर आज तक बीएसपी को यूपी के किसी भी विधानसभा चुनाव में 19 फीसदी से कम वोट नहीं मिले थे।

लोकसभा चुनाव से पहले 12 जनवरी 2019 को बसपा ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सपा के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियां गेस्ट हाउस कांड के 26 साल बाद साथ आई थीं। लेकिन, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। गठबंधन की बदौलत मायावती को सिर्फ 10 सीट ही मिल पाई। हालांकि, 2014 में शून्य पर सिमटी बसपा के लिए यह संजीवनी की तरह ही रहा। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की थी और पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ था, तो आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में आकाश का नाम मायावती के बाद दूसरे स्थान पर था। उन्हें विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कैडर को तैयार करने का काम भी सौंपा गया है।

मायावती के पास शुरू से ही दलित और मुस्लिम वोटबैंक का गठजोड़ रहा है। लेकिन अब उसका कोर वोट उनसे छिटक रहा है। यूपी में बसपा के कमजोर होने के चलते दलित समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक समय बसपा तीसरी ताकत के तौर पर उभरी थी, लेकिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दलित दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चले गये। उत्तराखंड और हरियाणा में उसका एक भी विधायक नहीं है। पंजाब में लंबे समय बाद उसका एक विधायक बना है। कर्नाटक में बसपा का 2018 में एक विधायक था, लेकिन 2023 के चुनाव में वो भी हार गया। बिहार में बसपा के टिकट पर जीते इकलौते विधायक ने जेडीयू का दामन थाम रखा है। कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस का साथ देकर सरकार बनवाई है। राजनीतिक गलियारों में प्राय: मायावती की सक्रियता को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। अब वे पहले की तरह चुनावी सभाओं में मौजूदगी नहीं दिखा पाती हैं। जानकारी के मुताबिक, 2022 में यूपी चुनाव के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं मायावती सिर्फ 18 बार रैली करती हुई दिखाई पड़ीं। फिलहाल, आकाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कामकाज देखेंगे। इन दोनों राज्यों में फिलहाल मायावती ही पार्टी के लिए निर्णय लेंगी।

हालिया विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समानांतर हिंदी पट्टी में चंद्रशेखर रावण ने युवा दलित नेता के तौर पर स्थापित होने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को चुनाव नतीजों से भारी निराशा हाथ लगी है। मायावती ने मौके की नजाकत को भांपते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद के रूप में अपने सबसे मजबूत सिपाही को आगे बढ़ाते हुए युवा दलित नेता के खाली स्थान को भरने का काम किया है। पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में आने के बाद अब देखना यह होगा कि आकाश अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कितना कमाल कर पाते हैं। चूंकि अभी लोकसभा चुनाव लगभग पांच महीने दूर हैं। इस अवधि में आकाश के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। आकाश बसपा के ग्राफ को कितना ऊंचा उठा पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।

ऑफ्थेल्मोलॉजी से दें कैरियर को एक नयी रोशनी

मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, पर स्पेशलाइजेशन के लिए विषय चुनने की कशमकश से गुजर रहे हैं, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान पर गौर कर सकते हैं. आंखों के विज्ञान पर केंद्रित यह विषय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इसमें आप दूसरों की आंखों की रोशनी को मुकम्मल करने के साथ एक खास पहचान भी बना सकते हैं. मेडिकल साइंस एक बड़ा कैरियर क्षेत्र है. इस क्षेत्र में कैरियर बनाने की जब बात होती है, तो इसके तहत आनेवाले क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र या विषय को चुनना होता है. ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान मेडिकल साइंस के तहत आनेवाला एक ऐसा ही विषय है. इसमें आइ स्पेशलिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑफ्थेल्मिकल टेक्नीशियन आदि बनने के मौके उपलब्ध हैं.

जानें कोर्स के बारे में

ऑफ्थेल्मोलॉजी में बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स से लेकर पीएचडी तक कर सकते हैं. साइंस (बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री) से 12वीं के बाद करनेवाले छात्र इसमें आगे बढ़ सकते हैं. ऑफ्थेल्मोलॉजी चुननेवालों में एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी) सबसे अधिक प्रचलित विकल्प है. एमबीबीएस के बाद आइ स्पेशलिस्ट बनने के लिए मास्टर कोर्स करना होता है. इसके लिए मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन क्लीनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी कर सकते हैं. आगे डॉक्टोरल कोर्स कर सकते हैं- मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम इन ऑफ्थेल्मोलॉजी. इस विषय में डिप्लोमा कोर्स भी संचालित होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑफ्थेल्मिक टेक्नोलॉजी आदि.

आपके लिए है यह विषय

ऑफ्थेल्मोलॉजी मेडिकल साइंस का विषय है. इसमें एमबीबीएस की डिग्री अहम है. इसके अलावा बीएससी या डिप्लोमा कोर्स कर के इसमें कैरियर बना सकते हैं. जाहिर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों के साथ 12वीं करनेवाले छात्र ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं. बैचलर डिग्री के बाद ही ऑफ्थेल्मोलॉजी में पीजी कोर्स का रास्ता बनता है.

ऐसे मिलेगा प्रवेश

किसी भी अच्छे संस्थान में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मिलेगा. देश के अधिकतर संस्थानों एवं कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा), एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) या या राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा आदि के आधार पर एडमिशन मिलता है.

प्रमुख संस्थान, जहां ले सकते हैं प्रवेश

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नयी दिल्ली. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम. आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी),पुणे. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी. अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, कोयंबटूर. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर. डी वाय पाटिल मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई. बीएससी इन ऑप्टोमीट्री कर सकते हैं.

आज जारी होगी एनडीए-सीडीएस भर्ती की अधिसूचना

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरफ से जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए-1) और संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस 1) भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना कल यानी 20 दिसंबर 2023 को जारी की जाएगी। एनडीए-1 और सीडीएस-1 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

UPSC NDA,CDS परीक्षा विवरण

यूपीएससी शेड्यूल अनुसार, एनडीए-एनए 1 और सीडीएस 1 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2024 तक है। एनडीए, एनए 1 और सीडीएस 1 के लिए परीक्षा 21 अप्रैल, 2024 को आयोजित की जाएगी। एनडीए और सीडीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र परीक्षा से तीन सप्ताह पहले जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

UPSC NDA,CDS आयुसीमा

एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष होनी चाहिए। सीडीएस परीक्षा के लिए, वायु सेना और नौसेना के लिए आवेदन करने वालों की आयु सीमा 19 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए उम्मीदवारों की आयु 19 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

यूपीएससी एनडीए एनए 1 और सीडीएस 1 भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को फोटो आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार की स्कैन की गई तस्वीर, सिग्नेचर और आईडी कार्ड, प्रमाणपत्रों के रूप में मैट्रिक और डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए।

UPSC NDA,CDS एजुकेशनल क्वालीफिकेशन

एनडीए परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सीडीएस के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। नौसेना में शामिल होने के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जबकि वायु सेना अकादमी के लिए स्नातक की डिग्री के साथ 12वीं कक्षा में भौतिकी और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए।

हर किसी के सामने कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब उसे अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है और तब मदद के लिए उसके दिमाग में सबसे पहले दोस्त व रिश्तेदार ही आते हैं. यदि आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसों की मदद मांगे, तो उनकी मदद जरूर करें, मगर यहां कुछ बातों का ध्यान रखें.

जब अपनों को दें उधार...

हर किसी के सामने कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब उसे अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है और तब मदद के लिए उसके दिमाग में सबसे पहले दोस्त व रिश्तेदार ही आते हैं. यदि आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसों की मदद मांगे, तो उनकी मदद जरूर करें, मगर यहां कुछ बातों का ध्यान रखें.

आमतौर पर लोग रिश्तेदारी में पैसों के लेनदेन से बचते हैं क्योंकि कई बार पैसा, बेहद करीबी रिश्तों में भी कड़वाहट घोल देता है, इसलिए लोग दोस्त या रिश्तेदारों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने से भी बचते हैं, मगर बावजूद इसके कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका कोई करीबी आपसे मदद मांगता है और आप रिश्तों का लिहाज करके ना नहीं बोल पातें. अपनों की मदद करना अच्छी बात है, मगर पैसों के मामले में थोड़ी एहतियात भी बरतनी चाहिए, यदि आपको किसी अपने को उधार देना ही पड़ें, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

ब्याज न वसूलें

आपने कोई बिजनेस डील नहीं की है और न ही किसी बैंक या फायनेंस कंपनी में निवेश किया है कि आपको ब्याज मिलेगा. अपने किसी सगे-संबंधी को दिए पैसों पर ब्याज वसूलने की गलती न करें, हो सकता है उस वक्त वो शख्स आपकी बात मान ले, मगर आगे चलकर निश्चित ही आपके रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी. ये बात भी आपको सोचना चाहिए कि उन्होंने बैंक या किसी फायनेंशियल कंपनी की बजाय आपसे पैसे इसलिए मांगे क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास है कि आप उनकी मजबूरी समझेंगे और उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे.

उधार को आदत न बनाएं

हालांकि आप अपने किसी करीबी को पैसे देकर उसकी मदद कर रहे हैं, मगर उधार देने को अपनी आदत में शुमार न करें. वरना सामने वाला व्यक्ति आपको ग्रांटेड लेने लगेगा. वो पैसों की अहमियत भी नहीं समझेगा क्योंकि उसे पता है कि जब उसे जरूरत होगी तो आप तो हैं ही उसकी मदद करने लगता है. इस स्थिति में कई बार उधार लेने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है. ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां उधार लेने वाले व्यक्ति ने तंगहाली के कारण पैसे देने वाले को ही रास्ते से हटा दिया है.

पहचान वालों को बनाएं गवाह

आप जो उधार दे रहे हैं यदि उसके लिए कोई लिखित सबूत नहीं है, तो कभी भी अकेले में पैसे उधार न दें, भले ही वो आपके भाई या बहन ही क्यों न करने के लिए और ये हालात आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय पैसे न चुकाने पर यदि आप उसे बार-बार याद दिलाते हैं, तो वो अपमानित और असुरक्षित महसूस हो.

जहां तक संभव हो ऐसे कुछ लोगों के सामने पैसे दें, जो आप दोनों को जानते हों. इससे पैसे लेने वाले को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहेगा और वो जल्द पैसे वापस करने की कोशिश करेगा. इसी तरह इन्हीं जानकार लोगों के सामने पैसे वापस लौटाने पर उधार वापस करने वाले को भी तसल्ली रहती है.

पहले अपनी सहूलियत देखें

'अरे चाचा जी ने आज पहली बार मुझसे पैसे मांगे है, अब तो किसी भी तरह से पैसों का इंतज़ाम करना ही पड़ेगाज' अपने किसी करीबी द्वारा उधार मांगने पर ऐसा रिएक्शन आपको मुश्किल में डाल देगा. मान लीजिए आपने अभी तो अपनी क्षमता से बाहर जाकर अपने किसी दोस्त या कलीग से पैसे मांगकर उन्हें दे दिए, लेकिन यदि सामने वाले ने आपको समय पर पैसे नहीं लौटाएं तब आप क्या करेगें. अतः यदि आपके पास पैसे नहीं है तो इन्कार करने में संकोच न करें. अपनी जरूरते पूरी होने के बाद यदि आपके पास अतिरिक्त पैसे हो तो ही किसी को उधार दें. यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार ने जितने पैसे मांगे हैं, आपके पास उतना नहीं है, तो उनसे साफ शब्दों में कह दीजिए कि आपके पास फिलहाल उतने पैसे नहीं हैं और जितना आपसे बन पड़े उतने ही पैसे दें.

शर्तों और नियमों पर चर्चा कर लें

पैसों के मामले में भावनाओं को दूर ही रखें. आपकी क्या शर्तें और नियम है इसकी लिस्ट बना लें, जैसे- वो कितने दिनों में आपके पैसे लैटाएंगे, पेमेंट कैसे करेंगे? यदि ज़्यादा अमाउंट है तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी आदि आदि. ये सारी चीजें सामने वाले से डिस्कस कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश न रहे. एक बात याद रखिए कि एक बार पैसे देने के बाद उससे बार-बार ये न पूछे कि उसने पैसों का क्या किया, कैसे खर्च किए. आपके बार-बार पूछने से रिश्ते में तनाव और दरार आ सकती है. यदि बहुत बड़ी रकम उधार दे रहे हैं, तो उसका लिखित सबूत यानि की रिटेन प्रूफ जरूर रखें.

पैसे वापस करने का समय निश्चित करें

चूंकि आप किसी अपने को ही उधार दे रहे हैं तो ऐसे में शायद आपको लगे कि पैसे वापस करने का समय निश्चित करने की जरूरत नहीं है, मगर आपकी ये सोच सही नहीं है. आप चाहे किसी को भी उधार दें, पैसे देते समय ही उसे वापस करने का समय भी तय कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला भी समय तय करने की जरूरत को समझें. दरअसल, ऐसा करना उसके लिए भी फायदेमंद ही रहेगा क्योंकि समय तय करने से उस पर निश्?चित तारीख तक पैसे देने का दबाव बढ़ेगा और आपके पैसे वापस चुकाने के लिए सेविंग करने में जुट जाएगा. जहां तक संभव हो कम पैसों के लिए ज्यादा लंबा समय न रखें. हां, यदि पैसे ज्यादा दिए हैं, तो आप साल दो साल का समय तय कर सकते हैं. आपने कितना उधार दिया है, ये हमेशा याद रखें.

परिस्थितियों का आकलन करें

किसी अपने को उधार देने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह से विश्?लेषण कर लें, साथ ही मामले की गंभीरता को भी समझने की कोशिश करें. क्या सामने वाले को सचमुच किसी बेहद ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए या फिर बस अपना कोई शौक पूरा करने लिए वो आपसे पैसे मांग रहा है. हालांकि इस मामले में बहुत ज्यादा पूछताछ न करें, मगर इतना जरूर जानने की कोशिश करें कि उसे किस काम के लिए पैसे चाहिए? हो सके तो उसे तुरंत पैसे देने की बजाय कोई दूसरा रास्ता सुझाएं. यदि फिर भी बात न बनें और पैसे देने ही पड़े, तो अच्छी तरह से उसकी जरूरत की पड़ताल करने के बाद ही पैसे दें, कहीं ऐसा न हो कि वो आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करे, जिससे भविष्य में आपके रिश्ते में दरार पड़ जाए.

सोनोग्राफी डॉक्टर को रोग की जड़ तक पहुंचाने का पेशा

जरूरी गुण निरीक्षण करने की बेहतर दृष्टि अच्छा संवाद कौशल मरीजों के प्रति नरम रवैया लंबे समय तक काम करने की शारीरिक क्षमता अपने क्षेत्र की नई तकनीकों की जानकारी धैर्य और सहनशीलता रोगियों का विश्वास जीतने का हुनर

अल्ट्रासाउंड टेक्निशियन को ही सोनोग्राफर कहा जाता है। पैरामेडिकल क्षेत्र के ये पेशेवर कुछ विशेष उपकरणों की मदद से मरीजों के रोगग्रस्त अंगों की तस्वीरें लेते हैं। सोनोग्राफी रोग का पता लगाने की एक जांच विधि है। इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल में लाई जाती है, उससे अल्ट्रासाउंस वेव्स (उच्च फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें) उत्पन्न की जाती हैं। जब इन तरंगों को शरीर के किसी खास हिस्से के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, तो सोनोग्राफी मशीन से जुड़ी एक स्क्रीन पर संबंधित अंग, टिश्यू और शरीर के उस हिस्से में हो रहे रक्त संचार की तस्वीरें नजर आने लगती हैं। तस्वीरें लेने की इस प्रक्रिया को ही चिकित्सा क्षेत्र की कामकाजी शब्दावली में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड स्कैन कहा जाता है।

इसी तरह इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले पेशेवरों को सोनोग्राफर कहा जाता है। जिन सोनोग्राफरों के पास इमेजिंग और रक्त शिराओं का टेस्ट करने में विशेषज्ञता होती है, उन्हें वस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। सोनोग्राफी की जरूरत रोगी के शरीर (खासकर रोगप्रभावित अंग) को अंदर से देखने की यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें शरीर के साथ किसी भी तरह की चीर-फाड़ करने की जरूरत नहीं होती। सोनोग्राफी की इस खासियत के कारण इसका इस्तेमाल शरीर के कई अंगों मसलन पेट, स्तन, हृदय, रक्त नलिकाओं, प्रजनन संबंधी अंगों और पौरुष ग्रंथि आदि की जांच के लिए किया जाता है।

हृदय रोगों, हृदयाघात और नाड़ी संबंधी रोगों की पहचान और उनके उपचार में सोनोग्राफी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं कैंसर की जांच के लिए होने वाले बायोप्सी टेस्ट में भी सोनोग्राफी मददगार साबित हो रही है। कैंसर की आशंका वाले अंग में बीमारी का पता लगाने के लिए एक बारीक सुई की सहायता से संबंधित अंग से कोशिकाओं (सेल) का थोड़ा-सा नमूना लिया जाता है, जिसकी बाद में प्रयोगशाला में जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब सुई को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब सोनोग्राफी के माध्यम से ही देखा जाता है कि सुई तय स्थान पर पहुंच रही है या नहीं। स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र (सोनोग्राफी में) ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिक सोनोग्राफी

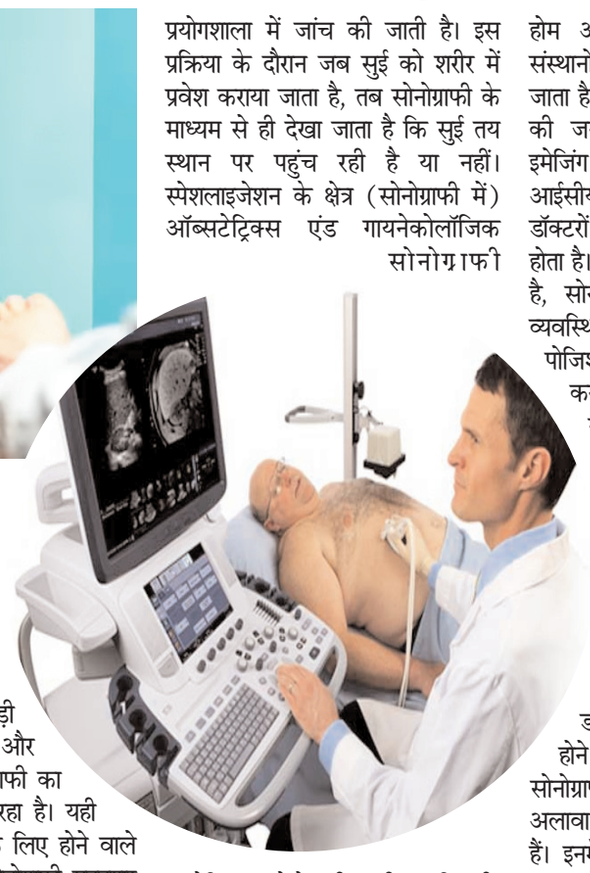

एब्डोमिनल सोनोग्राफी (लीवर, किडनी, गालब्लैडर और पैनक्रियाज) न्यूरोसोनोग्राफी (मस्तिष्क) ब्रेस्ट सोनोग्राफी वस्कुलर सोनोग्राफी (ब्लड वेसल्स) कार्डियक सोनोग्राफी (हर्ट) सोनोग्राफर का काम अस्पताओं, नर्सिंग होम और तमाम छोटे-बड़े चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफर को नियुक्त किया जाता है। वहां वह अपने नियोक्ता संस्थान की जरूरत के अनुसार डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू (इंटेंसिव केअर यूनिट) आदि में डॉक्टरों और नर्सों के साथ काम करना होता है। उनके काम का मुख्य हिस्सा होता है, सोनोग्राफी के लिए उपकरणों को व्यवस्थित करना और मरीजों को सही पोजिशन में आने के लिए निर्देशित करना, ताकि बेहतर जांच रिपोर्ट मिल सके। इसके अलावा वह सोनोग्राफी के दौरान स्क्रीन पर यह भी देखते हैं कि रोगी के जिस अंग का चित्र (इमेज) लिया गया है, उससे रोग की पहचान संभव होगी या नहीं। वह लिए गए कई चित्रों में से उन्हीं चित्रों को अंतिम रूप से चुनते हैं, जिनके आधार पर डॉक्टर मरीज में रोग के होने या न होने के निष्कर्ष तक पहुंच सकें। सोनोग्राफर को अपने मूल कार्यों के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य भी करने होते हैं। इनमें रोगियों के रिकॉर्ड को रखना, उपकरणों का रख-रखाव और मरीजों को जांच के लिए समय देना आदि शामिल होता है। कई बार उन्हें पूरे डायग्नोस्टिक इमेजिंग विभाग के प्रबंधन संबंधी कार्यों को भी देखना होता है।

● अश्विनी भावे

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने 7 जनवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने के निर्देश वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष संसद से उनके निष्कासन की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के लंबित होने पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि उनकी वर्तमान याचिका पर निर्णय देने से सीधे तौर पर शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही बाधित होगी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निष्कासित सांसद की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि मैं क्या करूँ सर? आपने रिट याचिका दायर करके आदेशों को चुनौती दी है। यदि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में स्टे देता है, तो आपका निलंबन रोक दिया जाएगा। अगर हम इस पर निर्णय देते हैं, तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करेगा।

पीएम मोदी से आज 10 सांसदों के साथ मिलेंगी ममता बनर्जी

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बकाया फंड की मांग को लेकर बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता ने नयी दिल्ली में पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के 10 सांसदों को प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, जिनमें पांच महिला सांसद भी रहेंगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंद्योपाध्याय, सौगत राय, डेरेक ओ ब्रायन, प्रकाश चिक बराइक, काकोली घोष दस्तिदार, शताब्दी राय, साजदा अहमद, प्रतिमा मंडल का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को बुधवार 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे संसद में पीएम मोदी से मिलने का समय मिला है। वह केंद्र से पश्चिम बंगाल के लंबित फंड के मुद्दे पर चर्चा करने वाली है।

इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है। हालांकि, वह 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र में जाने की अपनी योजना जारी रखेंगे। पार्टी नेता नेता राघव चड्ढा ने पुष्टि की। चड्ढा ने कहा कि आप सुप्रीमो के विपश्यना शिविर की योजना पहले से तय थी और नेताओं से कानूनी सलाह ली जा रही है। केजरीवाल लंबे समय से विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं, जो एक प्राचीन भारतीय ध्यान तकनीक है जिसमें अभ्यासकर्ता मानसिक कल्याण को बहाल करने के लिए लंबे समय तक संचार के किसी भी माध्यम से दूर रहते हैं और बेंगलुरु सहित कई ऐसे शिविरों में गए हैं। आप नेता हर साल 10 दिन का विपश्यना कोर्स करते हैं। इस वर्ष का पाठ्यक्रम 19 से 30 दिसंबर तक निर्धारित है। इस बीच, ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया है।

दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। नड्डा के साथ उनकी इस मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। चौहान ने पहले भाजपा प्रमुख के साथ अपनी निर्धारित बैठक की पुष्टि की थी लेकिन एजेंडे का खुलासा करने से परहेज किया था। चौहान ने सोमवार को भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा प्रमुख नड्डा ने बैठक के लिए बुलाया है और मैं उनसे मिलने जाऊंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद पाने के बारे में चर्चा की जाएगी, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी जीत दिलाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चौहान की यह पहली दिल्ली यात्रा है। पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर चल रही तेज अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह उसके लिए तैयार हैं।

कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री पोनमुडी को दोषी ठहराया

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया, जिससे उनकी बरी का फैसला पलट गया। 28 जून को वेल्लोर की एक प्रमुख सत्र अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। मद्रास उच्च न्यायालय ने अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और सजा इस सप्ताह के अंत में सुनाई जाएगी। वेल्लोर के प्रधान जिला न्यायाधीश एन वसंतलीला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री के. पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला किया।

विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक और एक्शन, थरूर, डिंपल, सुप्रिया सहित 49 निलंबित

लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित

नईदिल्ली। संसद में विपक्षी इंडिया गुट की ताकत मंगलवार को और कम हो गई। अनियंत्रित व्यवहार और सभापति के निर्देशों की अवहेलना के लिए अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों से अभूतपूर्व रूप से 78 सांसदों के निलंबन के बाद हुआ है। लोकसभा में सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ति चिदंबरम, सुदीप बंधोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित 49 विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।

लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अगर उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री) घटना (सुरक्षा उल्लंघन) पर संसद में बयान दिया होता तो क्या होता? सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाया गया

था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में कहा, सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हालिया चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम (सांसदों को निलंबित करने का) प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके साथ, संसद से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है। सोमवार को 46 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से और 45 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। जैसे ही विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा और उनसे संसदीय प्रक्रियाओं के हित में सांसदों के निलंबन के मामले को संबोधित करने को कहा। पवार ने कहा कि कुछ सांसद जो सदन के वेल में मौजूद नहीं थे या व्यवधान पैदा करने में शामिल थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया।

मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में देखे गए व्यवधानों और अनियंत्रित व्यवहार की एक श्रृंखला के बाद रिकॉर्ड निलंबन हुआ है। सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने और विधायी कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन दंडात्मक उपायों को आवश्यक बताया है।

निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का उड़ाया मजाक

नईदिल्ली। ऐसा लगता है कि विपक्ष ने संसदीय परम्पराओं को तार तार करने और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की प्रतिज्ञा ले ली है। पहले सदन में अमर्यादित आचरण किया गया जिसके चलते दोनों सदनों से उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन के कारणों पर आत्म चिंतन करने और अपना व्यवहार सुधारने की बजाय विपक्ष के नेताओं ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है जिससे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे लोग जिन्हें सदन के नियमों, परम्पराओं और आसन के सम्मान की कोई परवाह नहीं है, वह संसद के सदस्य रहने लायक भी हैं या नहीं? हम आपको बता दें कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे और इस दौरान वहां मौजूद अन्य निलंबित सांसद ठहाके लगा रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया और कल्याण बनर्जी द्वारा की जा रही मिमिक्री का वीडियो बनाने लगे। इस घटनाक्रम को देखकर सभापति ने सदन में सवाल किया कि राजनीति में और कितनी गिरावट आयेगी।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध को उचित ठहराने के 'प्रयासों' पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह उतना ही चिंताजनक है जितना की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा है।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ा था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने

वाले हर व्यक्ति को सामूहिक रूप से निंदा करनी चाहिए थी।

हम आपको यह भी बता दें कि संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष निलंबित सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। कई विपक्षी सांसदों के हाथों में तख्तियां थीं जिन 'डेमोक्रेसी अंडर सीज' (लोकतंत्र को बंधक बनाया गया) और कुछ अन्य नारे लिखे हुए थे। उन्होंने 'गृह मंत्री इस्तीफा दो' के नारे भी लगाए गए। खरगे ने कहा, ''हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सुरक्षा चूक के विषय पर गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। वह क्यों भाग रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। संसद का सत्र जारी है, लेकिन वह सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जो बातें सदन में बोलनी हैं, वह बाहर बोली जाती हैं तो इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती हैं।'' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सांसदों का निलंबन लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने का षड्यंत्र है तथा पहले गुजरात में भी इसी तरह से विधानसभा चलाई जाती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ''यहां तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ लड़ेंगे।''

नई सोच के चलते भारत 10 साल में 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की नौजवान पीढ़ी, देश के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान देने के लिए दिन-रात एक कर रही है। पहले जो हैकाथॉन्स हुए उनसे मिले समाधान बहुत कारगर रहे हैं। हैकॉथॉन्स में शामिल कितने ही छात्र ने अपने स्टार्ट अप्स भी शुरू किए हैं। ये स्टार्ट अप्स, ये समाधान, सरकार और समाज, दोनों की ही मदद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का लक्ष्य देश की समस्याओं का समाधान और समाधान से रोजगार निर्माण है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से देश की युवाशक्ति, विकसित भारत के लिए समाधान का अमृत निकाल रही है। मुझे आप सभी पर, देश की युवाशक्ति पर, अटूट भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भरोसा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के लिए कम लागत, गुणवत्ता, टिकाऊ समाधान प्रदान कर सकता है। युवा नवोन्मेषकों की समस्या सुलझाने की क्षमता, जटिल चुनौतियों से निपटने की प्रतिभा उल्लेखनीय है। ऐसे में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को किसी भी तकनीक का आयात न करना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अहम मुद्दा है।

यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, खड़गे ने संसद से सांसदों के निलंबन पर कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के दोनों सदनों से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र में सत्ता की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि संसद में जो कुछ हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। मीडिया के अनुसार विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड ले रखा था। जिन पर लिखा था, लोकतंत्र घेरे में है, हम पिंजरे में नहीं बंधेंगे, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप क्यों हैं। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यह संसद का अपमान है। वे हमें डराने के लिए सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आना नहीं चाहते थे। वे संसद के चालू सत्र के बीच वाराणसी और अहमदाबाद में व्याख्यान दे रहे हैं। अब तक कई सांसदों ने संसद में अपनी राय रखने की कोशिश की है।

खेल
प्रमुख समाचार

मिचेल स्टार्क बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

दुबई। मिचेल स्टार्क अब अपने हमवतन पैट कमिंस को पीछे छोड़कर आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। फिलहाल उनकी कीमत 22.50 करोड़ रुपये है और वह गुजरात टाइटंस के साथ हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया था। सनराइजर्स हैदराबाद (स्क्रा।) ने उन्हें 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबई में चल रही आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा।

पंजाब किंग्स ने भारत के मध्यम गति के गेंदबाज हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा। अल्जारी जोसेफ को आरसीबी ने 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा। हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड को मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के दौरान 6.80 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम से जोड़ा जबकि वेस्टइंडीज के रोवमैन पावेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा। गेराल्ड कोएत्जी को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपये में खरीदा। कोएत्जी का बेस प्राइस दो करोड़ रुपये था। ट्रेंस्टिन स्टब्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। केएस भरत को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 50 लाख की कीमत में खरीदा। चेतन सकारिया को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा।

नीलामी में सबसे पहला नाम वेस्टइंडीज के ञ्च20 कप्तान पावेल का था जिनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था। उनको खरीदने के लिए तीन टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। आखिर में राजस्थान रॉयल्स की टीम इस 'बिग हिटर' को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रही।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 122 अंक चढ़ा निफ्टी 21,500 के नीचे

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर बंद हुआ । वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में लिवाली से बाजार में तेजी आई। कारोबार के दौरान दोनों मानक सूचकांकञ्सेंसेक्स और निफ्टीजरिकॉर्ड स्तर पर चले गये थे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 122.10 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 71,437.19 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 308.62 अंक चढ़कर अपने अबतक के उच्चतम स्तर 71,623.71 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी कारोबार के दौरान 86.4 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 21,505.05 अंक तक पहुंचा। हालांकि, अंत में यह 34.45 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 21,453.10 अंक पर बंद हुआ।

एसबीआई के शेयर नए शिखर पर, 1 महीने में 17% बढ़ोतरी

नईदिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के शेयर मंगलवार को इंट्रा डे ट्रेड में बीएसई पर लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 659.50 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। मीडियम टर्म में बेहतर लाभ मिलने की उम्मीदों के बीच फिलहाल इस बैंक के शेयरों में जबरदस्त लिवाली देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) के शेयर ने 17 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी तुलना में, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी50 लगभग 9 फीसदी ऊपर हैं, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस अवधि के दौरान 14 फीसदी बढ़ा है। शेयरों की कीमतों में तेज उछाल ने एसबीआई के बाजार पूंजीकरण को 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है।

वेदांता को एनसीडी के जरिए रुपये जुटाने की मिली मंजूरी

नईदिल्ली। खनन समूह वेदांता लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की एक समिति ने गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) के जरिए 3,400 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी निजी नियोजन के आधार पर एक या अधिक बार में गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करेगी। वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा, निदेशकों की विधिवत अधिकृत समिति ने आज अपनी बैठक में निजी नियोजन के आधार पर अंकित मूल्य के 3,40,000 सुरक्षित, बिना रेटिंग वाले, असूचीबद्ध, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जुटाने पर विचार किया और मंजूरी दे दी। इसकी कुल कीमत 3,400 करोड़ रुपये बैठती है। वेदांता समूह की प्रमुख कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने पिछले सप्ताह ही बताया था कि वह अपने कर्जों की अदायगी के लिए 1.25 अरब डॉलर की फंडिंग हासिल करने में सफल रही है।

सरकार ने डीजल और कच्चे तेल पर घटाया विंडफॉल टैक्स

नईदिल्ली। सरकार ने सोमवार को देश में उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर 5,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,300 रुपये कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर एसएईडी को 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, जेट ईंधन के निर्यात पर लेवी पहले के शून्य से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर एसएईडी शून्य रहेगा। नई टैक्स दरें मंगलवार से लागू हो गई है। भारत ने पहली बार पिछले साल 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था और यह उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया है जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।

अब भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण भी पहुंचा विश्व में पांचवें स्थान पर

प्रह्लाद सबनानी

भारत आज विश्व के कई देशों को विभिन्न क्षेत्रों में राह दिखाता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में भारतीय शेयर (पूंजी) बाजार, नैशनल स्टॉक एक्स्चेंज, ने 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के पूंजीकरण के स्तर को पार कर लिया है। विदेशी निवेशक एवं विदेशी संस्थान जो माह सितम्बर 2023 तक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे, अब अचानक भारी मात्रा में भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। आज कई बार तो एक दिन में 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि का निवेश इन विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किया जा रहा है।

नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज पर लिस्टेड समस्त कम्पनियों (निफ्टी) का कुल बाजार पूंजीकरण 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अथवा 335 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इन कम्पनियों का पूंजीकरण 17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की संयोजित (कंपाऊडेड) दर से बढ़ा है। भारतीय शेयर बाजार के विकास की यह रफ्तार अभी भी जारी है और कलेंडर वर्ष 2023 के अभी तक के कार्यकाल के दौरान निफ्टी पर रजिस्टर्ड कम्पनियों के पूंजीकरण, 55 लाख करोड़ रुपए (11 प्रतिशत) से बढ़ चुका है। पिछले केवल 3 माह के दौरान भारतीय कम्पनियों का निफ्टी पर पूंजीकरण 8.82 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि विश्व के 10 सबसे बड़े शेयर बाजार में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ा है। आज भारत विश्व के शेयर बाजार के पूंजीकरण में 3.61 प्रतिशत का योगदान कर रहा है जो जनवरी 2023 में 3.37 प्रतिशत था।

नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज पर लिस्टेड समस्त कम्पनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का स्तर 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के

स्तर पर जुलाई 2017 में पहुंचा था और लगभग 4 वर्ष पश्चात अर्थात मई 2021 में 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया था तथा केवल लगभग 2.5 वर्ष पश्चात अर्थात दिसम्बर 2023 में यह 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को भी पार कर गया है। भारत शेयर बाजार पूंजीकरण के मामले में आज पूरे विश्व में पांचवें स्थान पर आ गया है।

प्रथम स्थान पर अमेरिकी शेयर बाजार है, जिसका पूंजीकरण 47.78 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पूरे विश्व में अमेरिकी शेयर बाजार का योगदान, शेयर के पूंजीकरण के मामले में, 44.74 प्रतिशत है और अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का अमेरिकी शेयर बाजार का पूंजीकरण 188 प्रतिशत है। द्वितीय स्थान पर चीन का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 9.73 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस वर्ष 2023 में चीन के शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को रिणात्मक प्रतिफल दिए हैं। पूरे विश्व में चीन के शेयर बाजार का योगदान 9.12 प्रतिशत है और चीन के सकल घरेलू उत्पाद का चीनी शेयर बाजार का पूंजीकरण केवल 54 प्रतिशत है। तीसरे स्थान पर जापान का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 6.02 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पूरे विश्व में जापान के शेयर बाजार का योगदान 5.64 प्रतिशत है और जापान के सकल घरेलू उत्पाद का जापान के शेयर बाजार का पूंजीकरण 142 प्रतिशत है। चौथे स्थान पर हांगकांग का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 4.78 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पूरे विश्व में हांगकांग के शेयर बाजार का योगदान 4.48 प्रतिशत है और हांगकांग के सकल घरेलू उत्पाद का हांगकांग शेयर बाजार का पूंजीकरण 1329 प्रतिशत है। जबकि भारत, फ्रान्स एवं ब्रिटेन के शेयर बाजार को पछाड़कर पांचवे स्थान पर आ गया है। आज भारत के शेयर बाजार का पूंजीकरण 4.10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पूरे विश्व में भारत के शेयर बाजार का योगदान 3.61 प्रतिशत है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण 114 प्रतिशत है। जिस तेज गति से भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण आगे बढ़ रहा है, अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण हांगकांग शेयर बाजार के पूंजीकरण को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आ जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व मंत्री अकबर ने दी खुली चुनौती

'प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान है तो सामने लाए भाजपा सरकार'

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत मध्यप्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड़ जीत हासिल की है। वहीं, सत्ता में फिर से वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से पार्टी के नेता एक तरफ नाराज हैं तो वहीं, हार का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। हार के बाद कई कार्यकर्ताओं के विवादित बयान भी सामने आए थे, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया था।

इसी बीच अब कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान सामने आया है।

अपने बयान में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भाजपा को चुनौती दी है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, कि प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान है तो सामने लाए। प्रदेश में रोहिंग्या को बसाने का भाजपा ने मुझ पर आरोप लगाया था।

पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, कि भाजपा बताए की कितने रोहिंग्या मुसलमान है? उन्होंने कहा कि ये तो बस राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप पर अकबर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस झूठी कहानी का सहारा लेते हैं और इस बार भी यही हुआ।

नेशनल लोक अदालत में कुल 4,85,813 प्रकरणों का हुआ निराकरण

कुल 7 अरब, 89 करोड, 98 लाख 37 हजार 892 रूपये का अवार्ड पारित

रायपुर। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में नालसा द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर तक सभी न्यायालयों में 16-12-2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये हैं।

अवलोकनीय है कि सालसा के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के द्वारा जिला न्यायालय धमतरी एवं कांकेर का भ्रमण कर उक्त लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण किया गया, इस दौरान उनके द्वारा न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों का लोक अदालत के प्रति उत्साहवर्धन किया गया साथ ही दाम्पत्य प्रकरणों के निराकरण पर पक्षकारों को पौधा प्रदान किया गया। उपरोक्त लोक अदालत में पिछले आयोजित तीन लोक अदालत की तुलना में सबसे ज्यादा कुल 4,85,813 प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें प्री-लिटिगेशन के 4,34,931 एवं लंबित मामलों के 50,882 प्रकरणों शामिल है जिसमें कुल 7 अरब, 89 करोड, 98 लाख 37 हजार 892 रूपये का अवार्ड पारित किया गया है।

इस लोक अदालत के संबंध में सालसा के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के द्वारा यह भी बताया गया कि सालसा के द्वारा इस बार विशेष तौर से 5 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक अवधि के तथा वरिष्ठजनों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत किये जाने हेतु विशेष अभियान के तहत उक्त लोक अदालत में 5 वर्ष अवधि वाले 932, 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले 82 तथा वरिष्ठजन के 328 प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकृत किये गये हैं, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में पूर्व आयोजित तीनों लोक अदालतों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला न्यायाधीशों एवं फैमिली कोर्ट न्यायाधीश को सम्मानित करने के लिये सालसा द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर सम्मानित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस बार की लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है।

धान खरीदी और बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक

25 दिसम्बर को होगा दो साल के बकाया बोनस राशि का वितरण

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसानों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई.

मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राज्य अतिथि गृह (पहुना) में जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले से आए रामनामी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात कर मुख्यमंत्री को नयी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को नये वर्ष में आयोजित होने वाले समाज के मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने न्यौता दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न पंथो के साधु-संत भी शामिल हुए थे। इनमें रामनामी समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

आईएएस पी दयानंद बनाए गए मुख्यमंत्री सेक्रेटरी

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव की नियुक्ति की गई है. 2006 बैच के आईएएस पी दयानंद को सचिव मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ किया गया है. साथ ही सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं आईएएस सुब्रत साहू को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के प्रभार से मुक्त किया गया है. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

मुख्यमंत्री साय के ओएसडी और निज सहायक नियुक्त

रायपुर. राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ सुभाष सिंह राज, उमेश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नए ओएसडी होंगे. वहीं दीपक अंधारे को निज सहायक बनाया गया है. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने जारी किया है.

रायपुर जिले के 6 ग्रामों में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शिविर आयोजित

रायपुर. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से मिले रुपयों से मैं अपने छोटे से पार्लर को बड़ा और सुन्दर बनाउंगी, मेरा पार्लर - मेरा घर विकसित होगा, तभी तो बनेगा विकसित भारतश्, चहकते हुए कहा आरंग की सेवती वर्मा ने। श्रीमती वर्मा और अन्य महिलाएं ऋण और अन्य योजनाओं हेतु आवेदन देने, आरंग के नरदहा गाँव में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शिविर में आई थी। उल्लेखनीय है की रायपुर जिले में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' पूरी गति से चल रही है और हर दिन विभिन्न क्षेत्रों एवं गांवो में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनके क्रियान्वयन की गति को तेज करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज अभनपुर के भुरका एवं भुतहीडीह में, आरंग के नरदहा एवं सेमरिया में और तिल्दा के बेमता एवं भूमिया गाँव में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, किसान

सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जॉच भी की गई। कार्यक्रम में आए ग्राम सेमरिया के श्री रोहित साहू ने बताया कि उन्होंने अपने जीवनकाल में पहली बार ऐसा शिविर देखा जहां एक ही छत के नीचे कई विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल रही थी। उन्होंने अपने बेटे पूरब साहू का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन देते हुए कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन और होना चाहिए।

जिले भर में आज लगाये गए शिविरों में पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं हेतु 300 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से उज्ज्वला गैस कनेक्शन में आधार लिंक, जल जीवन मिशन में दिक्कतें इत्यादि में तुरंत निराकरण किया गया।

प्रमुख समाचार
छत्तीसगढ़/राजधानी

कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई रणनीति

रायपुर. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई. बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कोंटा विधायक कवासी लखमा, खरसिया विधायक उमेश पटेल समेत अन्य विधायक मौजूद रहे. इसके अलावा पूर्व मंत्री रवींद्र चौबे,ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर,शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी है. राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर विस्तार से चर्चा हुई है. नारायणपुर में किसान आत्महत्या के मामले को भी उठाया जाएंगे. राज्यपाल के अभिभाषण किन बिंदुओं को रखा गया है, उस आधार पर भी चर्चा होगी. डॉ. महंत ने बैठक के बाद कहा, नए विधायकों को पूर्व सदस्यों का भी आशीर्वाद मिला. हमने लोगों ने हार की समीक्षा भी की. हम सब आश्चर्य चकित हैं कि हार कैसे हुई ? क्योंकि चुनाव को लेकर हम सबने कड़ी मेहनत की थी. सरकार चले जाने का दर्द है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे.

भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेसी निगम मंडलों को भंग करने की कवायद शुरू

रायपुर. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कुछ नेताओं ने खुद इस्तीफा दे दिया था,वहीं कुछ नेता अभी भी पदों पर बने हुए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को पत्र जारी करते हुए पुरानी नियुक्तियां समाप्त करने के आदेश दिए हैं। अब निगम, मंडल व आयोगों में भाजपा अपने नेताओं की नियुक्तियां करेगी। जानकारी के मुताबिक अलग-अलग विभागों में 200 से अधिक पदों पर पूरी तरह नियुक्ति होने में एक से डेढ़ महीने का वक्त लग सकता है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद नए सिरे से मंडलों व निगमों में पद बांटे जाएंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने निगम, आयोग व मंडल में कांग्रेस द्वारा की गई नियुक्तियां भंग कर दी है। अलग-अलग विभागों में कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं की नियुक्तियां की थी। रायपुर नगर निगम सहित अन्य निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने की मांग भाजपा नेता कर रहे हैं। अब भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेसी नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों को भंग करने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मानें तो प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस काबिज नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सुगबुगाहट चल रही है।

2 लाख रुपए लेकर दूसरे छात्र की जगह परीक्षा में बैठा मुन्ना भाई गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी पहचान हरियाणा के हिसार निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। 2 लाख रुपए लेकर आरोपी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आया था। दूसरी पाली की परीक्षा में उसने आधा पेपर लिख लिया था। तभी दिल्ली से फोन आया और सूचना मिलते ही उसका बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान लिया गया, जिसका मिलान नहीं हुआ। जिसके बाद शिक्षक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एएसपी लखन पटले ने बताया कि सीबीएसई एकलव्य आवासीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की भर्ती रविवार को आयोजित की गई थी। टाटीबंध स्थित महर्षि विद्या मंदिर को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहां हरियाणा के हिसार निवासी सुनील कुमार का भी परीक्षा केंद्र था। सुनील ने अपनी जगह हिसार के ही दीपक कुमार को परीक्षा देने भेजा था। उसने प्रवेश पत्र से लेकर सभी दस्तावेजों में अपनी फोटो लगाई थी। वह परीक्षा में शामिल हो गया, लेकिन जांच के दौरान पकड़ा गया।

छत्तीसगढ़ के 8 वाणिज्यिक गैर कोयला खदानों की नीलामी आज

रायपुर। कोयला मंत्रालय के द्वारा 20 दिसंबर को नई दिल्ली में वाणिज्यिक गैर कोयला खदानों नीलामी करेगा जिसमें छत्तीसगढ़ की 8 खदाने भी शामिल है। आगामी दौर में कुल 26 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिसमें सीएम (एसपी) अधिनियम 2015 के तहत 3 खदानें और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत 23 खदानें शामिल हैं। इनमें से 7 कोयला खदानों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई हैं, जबकि 19 खदानों को आंशिक रूप से पहचाना गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयले के सातवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत, 5 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है, जिसमें चार सीएमएसपी कोयला खदान और एक एमएमडीआर कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें से चार पूरी तरह से पहचान ली गई हैं और एक खदान को आंशिक रूप से पहचाना गया है।

59 वेंडिंग जोन का निर्माण अब तक क्यों नहीं, अधिकारी जवाब दें: मीनल चौबे

रायपुर। नगर निगम मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने नगर निवेश के अधिकारियों से वेन्डिग जोन निर्माण को लेकर चर्चा की। श्रीमती चौबे ने अफसरों से पूछा कि इतने दिनों तक वेंडिंग जोन का निर्माण आखिर क्यों नही किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत खोमचे वाले, ठेलेवाले और रेहड़ी वालों को लोन की राशि उपलब्ध करायी गई है जिसके लिए शहर भर में टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से दस जोन में 59 स्थानों को वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित किया गया है। जिसमें 14 प्रक्षेत्रों को वेंडिंग क्षेत्र में निर्धारित करने का आदेश आयुक्त के द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर को कर दिया गया था। दूसरे आदेश में 13 क्षेत्रों को वेंडिंग प्रक्षेत्र निर्धारित करने का आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 को किया गया था। इसके बावजूद अधिकांश स्थानों मे शहर के गरीब ठेलेवालों एवं खोमचा वालों का व्यवस्थापन आज दिन तक नही किया गया है। हितग्राही आखिर कहां करेंगे व्यवसाय- नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने नगर निवेश अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दिसम्बर 2023 तक लगभग 15463 हितग्राहियों का लोन स्वीकृत किया गया है जिसमें से 14830 हितग्राहियों को लोन वितरित किया जा चुका है।

अवैध चखना सेंटरों को बंद कराने जारी रहेगी कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा ना हो अवैध कब्जा:कलेक्टर

रायपुर। रायपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने कार्रवाई को तेज करते हुए सभी अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद खाली भूमि-जगह पर निरंतर नजर रखने को भी कहा, ताकि उस

जगह पर दोबारा अवैध कब्जा ना हो। कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे चखना सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें वापस खुलने नहीं देना सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने शहर के भीतर सड़कों के किनारे और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चल रहे ढाबों और होटलों के बाहर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

यातायात अवरुध्द करने वाले ढाबों पर कार्यवाही के निर्देष- कलेक्टर ने यह भी कहा कि वाहनों के साथ-साथ ऐसे सभी ढाबा और होटल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाए, जिनके कारण यातायात व्यवस्था अवरूद्ध होती हो। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी सहित अपर कलेक्टर द्वय श्री बी.बी. पंचभाई एवं बी.सी. साहू, एडीएम एन.आर. साहू, पुलिस अधिकारी, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने दुकानों के बाहर सड़क तक सामान रखकर बेचनें वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदारों को एक बार चेतावनी देकर दूसरी बार सामान जब्ती की कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शहर में चल रहे ऑटो और रिक्शाओं के व्यवस्थित संचालन पर जोर दिया। इनके लिए प्रमुख चौक-चौराहों में स्टैण्ड की जगह सुनिश्चित करने और सड़कों पर स्टॉप सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए।

लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रायपुर रीजन और कोरबा पश्चिम के बीच होगी खिताबी भिड़ंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की तीन दिवसीय अंतरक्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन टीम मुकाबले हुए। टीम स्पर्धा में रायपुर रीजन और कोरबा पश्चिम ने अपने - अपने मुकाबले जीत कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय कला एवं क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक श्री जे एस नेताम तथा रायपुर केन्द्रीय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री के एस मनोठिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय क्रीड़ा सचिव श्री आर के बंछोर एवं रायपुर क्षेत्र के क्रीड़ा सचिव श्री विनय चंद्राकर समेत प्रदेश भर से आए खिलाड़ी मौजूद थे।

लॉन टेनिस प्रतियोगिता प्रभारी श्री मनोज वर्मा ने बताया कि 19 से 21 दिसंबर तक युनियन क्लब रायपुर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 क्षेत्रीय टीमों रायपुर रीजन, रायपुर सेंट्रल, बिलासपुर रीजन ,दुर्ग रीजन ,राजनांदगांव रीजन, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम के 40 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन टीम युगल स्पर्धा हुई। दूसरे दिन टीम स्पर्धा के फाइनल के साथ ही ओपन एकल तथा युगल स्पर्धाएं होंगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.